साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-31 अंक- 27 07 - 13 जुलाई 2024 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

बदलाव से ही "बदलेगी तस्वीर" पृष्ठ - 6

कुदरत के साथ बिगड़ता संतुलन पृष्ठ - 7

विधायी निकायों में आपराधिक छवि वाले नेताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी

लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती

आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विधायिका में 46 प्रतिशत आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग सदस्य के रूप में बैठे है, तो सोचिए देश का भविष्य क्या होगा।

18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सरकार का गठन भी हो चुका है और प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है और इतना ही नहीं, देश की जनता और मतदाता इस लोकतंत्र की रक्षा के तरीके भी जानते हैं और यही कारण है कि भारत में सत्ताधारी अभिजात वर्ग इस लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदृश्य रूप से राजशाही सी में बदलने की कोशिश की जा रही है।

मतदाता आगे आए और भावी किंगमेकरों का हाथ पकड़ लिया और या तो उन्हें सत्ता के सदन से बाहर कर दिया या उनसे कहा कि अगर वे बाज नहीं आए तो उन्हें सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। यह लोकतांत्रिक भारत के मतदाताओं के बीच एक स्थिर भावना है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक स्वागत योग्य पहलू है।

हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री मोदी, जिन्होंने अब तीसरी बार यह पद संभाला है। जब उन्होंने पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तो उन्होंने घोषणा की थी कि उनका पहला काम राजनीति से अपराधीकरण को साफ करना होगा। इसकी घोषणा किये हुए दस साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वे इस वादे को पूरा नहीं कर पाये हैं, लेकिन सच्चा यह है कि उन्होंने इस दिशा में कोई गंभीर कदम भी नहीं उठाया है, उनके पास सीबीआई और ईडी जैसी दर्जनों एजेंसियां हैं ये अच्छा काम कर सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ।

ये भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उनका इसका दायरा अभी भी उनके विरोधियों तक ही सीमित है, जिसे दूसरे शब्दों में एक नये प्रकार का राजनीतिक भ्रष्टाचार कहा जाना चाहिए। यदि माननीय प्रधान मंत्री ने अपना वादा निभाया होता और बिना किसी भेदभाव के राजनीति को अपराधों से मुक्त करने का बीड़ा उठाया होता, तो आज हमें दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे पांच लोगों की खबर का सामना नहीं करना पड़ता। संसद के (543) सदस्यों का छत्तीस प्रतिशत आपराधिक रिकॉर्ड है। ये आंकड़े पिछली संसद के हैं प्रतिशत अधिक है। जाहिर है, भारतीय राजनीति में अपराधियों की भागीदारी ऐसे लोगों और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है

उनसे विकास कार्य करने की अपेक्षा करना भारत के आत्मनिर्भर नागरिकों के लिए चिंता का विषय होगा। सवाल यह है कि इस रूप में हमारी राजनीति में कोई पारदर्शिता और शुचिता नहीं है।

आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? अम्लीय चुनावों से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में हमारे तैंतालीस (43) प्रतिशत प्रतिनिधि चुने गए।

18वीं लोकसभा के लिए चुने गए 251 सांसदों ने अपने आपराधिक मामले स्वीकार किए हैं, जो छियालीस फीसदी है। आश्चर्य की बात है कि आज राजनीति में आपराधिक तत्व इस हद तक बढ़ गए हैं कि हत्या और अपहरण जैसे अपराधों में शामिल तत्व अदालत में पेश होने के बजाय पद की शपथ

> हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री मोदी, जिन्होंने अब तीसरी बार यह पद संभाला है। जब उन्होंने पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तो उन्होंने घोषणा की थी कि उनका पहला काम राजनीति से अपराधीकरण को साफ करना होगा। इसकी घोषणा किये हुए दस साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वे इस वादे को पूरा नहीं कर पाये हैं, लेकिन सच्चा यह है कि उन्होंने इस दिशा में कोई गंभीर कदम भी नहीं उठाया है।

लेने जाते हैं। आख़िर हमारे राजनीतिक आका ऐसे लोगों को जिम्मेदार पद सौंपकर ईमानदारी और अच्छा प्रबंधन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में कोई जनता के विश्वास पर कैसे खरा उतर सकता है और ऐसे लोगों के लिए संसद के दरवाज़े कैसे बंद किये जा सकते हैं? हमें अपनी न्यायिक प्रणाली, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय की जागरूकता, परिश्रम और समय पर निर्णय लेने की शक्ति के लिए सराहना करनी चाहिए, यदि संसद या विधानसभा के उम्मीदवारों के पास कोई पिछला या हालिया आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उन्हें हलफनामे के रूप में इसका खुलासा करना चाहिए राजनीति को अपराधमुक्त करने के स्पष्ट उद्देश्य से चुनाव आयोग के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इच्छा थी कि को भी पाटह्ल किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले को उम्मीदवार न बनाये, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहल्ल हो सका. चूँकि हर पाटह्ल ऐसे उम्मीदवार के रूप में जाना जाना चाहती है जो जीतने में सक्षम हो, और क्योंकि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग अपने प्रभाव और भय की राजनीति का उपयोग करके सफल होते हैं, इसलिए हर पार्टी ऐसे लोगों को चाहती है। उम्मीदवार बना कर भूल जाते हैं कान से वाणी अधिक व्यापक हो जाती है। इस तथ्य को कैसे नकारा जा सकता है?

आज हमारा राष्ट्रीय जीवन इसी प्रकार चल रहा है जैसा कि हमारी सोच और चिंता आगे है।

वह मानव जीवन को बढ़ा रहा है सभी नियम नष्ट हो गए हैं, जो भी हो उसे देखकर हमारा भेद पुनः चिन्हित होता था, आज करोड़ों भारतीय नागरिक निराश हैं उनका आत्मचिंतन एक गहरी गुफा में डूबा हुआ। ज़ाहिर तौर से अगर देश को इस दलदल से बाहर निकालना है तो केवल प्रयास ही नहीं बल्कि त्याग देकर हमें इसकी कीमत भी देश को चुकानी पड़ेगी। नागरिकों को आगे आना होगा और ऐसा संघर्ष करना होगा जिससे देश में ऐसा माहौल बने कि न केवल राजनीति बल्कि देश में जीवन का हर क्षेत्र अपराध से मुक्त हो। वैसे तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री हर स्तर पर आपराधिक राजनीति और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन वह चुनाव जीतने के लिए हर मौके पर आपराधिक राजनेताओं को भी प्राथमिकता देते नज़र आते हैं, जो निस्संदेह इस बात का संकेत है कि वे क्या कहते हैं और क्या करते हैं यह एक ऐसा अंतर है जो किसी भी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं दे सकता।

यहां एक ही सवाल बार-बार मन को कचोटता रहता है कि क्या सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में ऐसे लोगों की भूमिका होगी? देश का भविष्य क्या होगा? क्या सत्ता में आने के बाद ये अपराधी लोग हमारी कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और अगर ऐसा होगा और होगा, तो जरा सोचिए कि हमारे समाज का क्या होगा, इसलिए सिद्धांतों के बारे में बात करना जरूरी है राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करे, साथ ही भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और शुचिता लाने के लिए सभी राजनीतिक दल सहमत हो। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति कोई, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, विधानसभा और संसदीय चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। यह समय की पुकार है और याद रखना चाहिए कि अगर इस दिशा में कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में दागी विधायकों

बाक़ी पेज 11 पर

12 जुलाई 2038 को ख़त्म हो जाएगी दुनिया : नासा

वाशिंगटन, : दुनियाभर में मच रही उथल पुथल और दो युद्धों के बीच अब नासा ने डराने वाली भविष्यवाणी की है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक, आज से 14 साल बाद यानी 12 जुलाई 2038 को एक खतरनाक क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकरा सकता है, जिसके चलते दुनिया खत्म हो सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस विशालकाय एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 72 प्रतिशत तक है और इसे रोक पाने के लिए धरती पर अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं है। नासा की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल में एजेंसी ने पांचवां प्लैनेटरी डिफेंस इंटर एजेंसी टेबलटॉप अभ्यास आयोजित किया था, जिसमें अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के लगभग 100 प्रतिनिधि शामिल थे। 20 जून को मैरिलैंड स्थित जॉन्स हॉपकिन्स एप्लाइड फिजिक्स वे लैबोरेटरी में इसके मुख्य निष्कर्ष जारी किए गए।

इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह एक्सरसाइज इस कारण की गई थी कि इस तरह के ख़तरे से निपटने के लिए हमारी धरती की क्षमता का आकलन किया जा सके। इस एक्सरसाइज के दौरान काल्पनिक परिदृश्य के लिए एक खास तरह का माहौल तैयार किया गया था। इस दौरान कभी नहीं पहचाने गए स्टेरॉयड की पहचान की गई और काम किया गया। इस रिपोर्ट ने जो शुरुआती गणना की उसके मुताबिक इस क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की 72 प्रतिशत संभावना है, जिसमें करीब 14 सालों का समय लगेगा। हालांकि, स्टेरॉयड के आकार, कॉम्पोजिशन और लॉन्गटर्म ट्रेजेक्टरी को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वॉशिंगटन स्थित नासा के हेड ऑफिस में प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडले जॉनसन ने कहा कि इस एक्सरसाइज की शुरुआती अनिश्चितताओं ने प्रतिभागियों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने का मौका दिया है। उनके मुताबिक एक बड़ा क्षुद्रग्रह संभावित रूप से एकमात्र प्राकृतिक आपदा है।

इस्लामी दुनिया ..... इस्लामी दुनिया ..... इस्लामी दुनिया

क्षेत्रीय असंतुलन और पाकिस्तान

करीबी मित्र को करीब रखने की चुनौती

भारत की 'पड़ोसी पहले' की नीति 1947 से का अहम हिस्सा रही है। यह पड़ोसियों से संबंध मजबूत बनाने, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, पड़ोसियों के साथ साझा मुद्दों का हल निकालने पर केंद्रित है, जिसे चीन की खतरनाक विस्तारवादी और कर्ज नीति से निपटने के लिए, शीर्ष प्राथमिकता देने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों एवं हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं की मौजूदगी से स्पष्ट है कि नई दिल्ली इन देशों को कितना महत्व देती है। समारोह में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मॉरिशस के प्रधानमंत्री एवं सेशेल्स के उपराष्ट्रपति और श्रीलंका तथा मालदीव के राष्ट्रपति मौजूद थे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू का शामिल होना रणनीतिक दृष्टि से इसलिए अहम था, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। भारत ने 'पड़ोसी पहले' की नीति के तहत दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर हमेशा जोर दिया है। इसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। अतीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्क नेताओं को निमंत्रण देना, दक्षिण एशिया में नई शुरुआत का संकेत था। मोदी के तीसरे कार्यकाल में दक्षिण एशिया के छोटे देशों के ज़रिये क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारतीय दृष्टिकोण में भू-राजनीतिक बदलाव की उम्मीद है। मालदीव की नकारात्कता के बावजूद भारत ने संयम बरता है, जिससे संबंधों में सुधार की गुंजाइश है। मालदीव और नेपाल चीन के प्रलोभन में फंसे हुए हैं। इसलिए भारत को क्षेत्रीय संतुलन बनाकर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना होगा। वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देना, इसके जवाब में मोदी का भी धन्यवाद कहना काफी -कुछ बयां करता है। नवाज शरीफ ने लिखा कि 'आइए, हम नफरत को आशा में बदलें और दक्षिण एशिया के दो अरब लोगों की नियति को आकार देने के लिए अवसरों का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत जवाब दिया कि 'भारत के लोग हमेशा शांति, सुरक्षा और प्रगतिशील विचारों के लिए खड़े हैं। अपने लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए आगे बढ़ाना हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी।'

उल्लेखनीय है कि 2014 में जब मोदी पहली बार श्प्रधानमंत्री बने, तो नवाज़ शरीफ भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बेहतर रिश्ते रहे हैं। मोदी ने पाकिस्तान से संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास भी किया था। वर्ष 2015 में मोदी अचानक, नवाज शरीफ को 66वें जन्मदिन की बधाई देने लाहौर पहुंचे थे और उनकी नातिन मेहरुनिस्सा की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए थे। हालांकि पाकिस्तानी सेना को यह पहल पसंद नहीं आई थी। इससे पहले 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा करके संबंधों में नरमी लाई थी।। कूटनीति के सिद्धांतों के अनुसार, भले ही दोनों देशों के बीच संबंधों की निरंतरता को शत्रुता नियंत्रित करती हो, फिर भी बातचीत जारी रहनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ईमानदारी दिखाए और सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करे, तो भारत फिर से बातचीत शुरू कर सकता है। विशेषज्ञ इस पर एकमत हैं कि चीनी राष्ट्रपति भारत के साथ शत्रुता का भाव रखते हैं, जबकि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होने पर अमेरिका भी सहज महसूस करेगा।

हालांकि अब स्थितियां बदली हैं और नवाज़ शरीफ और सेना भारत से रिश्ते में सुधार के लिए एकमत होते दिख रहे हैं, लेकिन आईएसआई को कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा देने वाले आतंकियों को समर्थन देना बंद करना होगा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से व्यापार रोक दिया। था। भारत अभी जल्दबाज़ी में पाकिस्तान के साथ व्यापार का कोई निर्णय भी नहीं लेगा।

नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पड़ोसी देशों पर गहरा असर हुआ है। मोदी अगले पांच वर्ष तक देश की कमान संभालेंगे, ऐसे में विदेश नीति पर पुनर्विचार करना समय की मांग है। साथ ही, सार्क देशों के साथ संबंध, सुधारते हुए पाकिस्तान के साथ गतिरोध खत्म करने की पहल करनी होगी, पर पाकिस्तान को कैश्मीर फोबिया से बचना होगा।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना पंद्रह दिनों के भीतर दूसरी बार भारत की यात्रा पर रही। प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच रिश्ते और मज़बूत करना चाहते हैं। पर यह इस पर भी निर्भर करता है कि भारत बांग्लादेश को क्या दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और हसीना, दोनों दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जटिल राजनीतिक व भू-राजनीतिक गतिशीलता से वाक़िफ हैं, जिसमें क्वाड चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। अनुमान लगाया जा सकता है कि चीन को अलग-थलग करने के लिए भारत ऐसे प्रस्ताव देगा, जिन्हें वह आसानी से मना नहीं कर पाएंगी। इससे हसीना को अगले महीने चीनियों से बातचीत में भी कुछ लाभ मिलेगा।

शेख़ हसीना ने चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्थगित कर दिया है। भारत रक्षा पर 50 करोड़ डॉलर की क्रेडिट लाइन का शीघ्र कार्यान्वयन चाहता है। हसीना ने तीस्ता नदी के विकास में वित्त पोषण और भागीदारी के चीन के प्रस्ताव को भी टाल दिया। समझौते के अनुसार, इसके पानी के समान बंटवारे की बांग्लादेश की पुरानी मांगे है। लेकिन भारत इसे पूरा करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इससे सहमत नहीं है। इस बार भी समझौते की संभावना नहीं दिखती है। वर्ष 2026 में गंगा जल संधि ख़त्म हो जाएगी, जिसे परस्पर संतुष्टि के लिए फिर से नवीनीकृत किया जाना चाहिए। यदि भारत इसमें चूक जाता है, तो चीन को बांग्लादेश को अपने पाले में लाने की कोशिश करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए भारत को अपने 'सबसे करीबी' और 'मित्रवत' पड़ोसी की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। भारत और बांग्लादेश, दोनों के पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण हैं, जिसे

बाक़ी पेज 11 पर

यह दिल्ली है ..... यह दिल्ली है ..... यह दिल्ली है

चार दशक में बढ़ी गर्मी, घर की बनावट में बदलाव ज़रूरी

राजधानी में गर्मी इसी साल एकाएक नहीं बढ़ी है, बल्कि पिछले चार दशकों के दौरान इसमें निरंतर इजाफा हो रहा। 1980 से 2023 के दौरान बढ़ी इस गर्मी की प्रमुख वजह बढ़ती आबादी और उसकी जरूरतों के लिए हुआ निर्माण कार्य है। 1987 सबसे गर्म साल था, जब सालाना औसत तापमान 32.78 डिग्री सेल्सियस रहा था। सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) ने अपनी एक पूर्व रिपोर्ट 'स्वैल्ट्रिंग नाइट्सः डीकोडिंग अर्बन हीट स्ट्रेस इन दिल्ली' में बताया है कि दिल्ली में जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम तेजी से बदल रहा है। तापमान ही नहीं, वातावरण में मौजूद नमी में भी तेजी से इज़ाफा हो रहा है। अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन ने शहर को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म और नम बना दिया है। दरअसल, पिछले चार दशकों में दिल्ली में कंक्रीट का जंगल भी बढ़ा है, जो अर्बन हीट आईलैंड प्रभाव में भी इजाफा कर रहा है। 2000 के बाद दिल्ली में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। निर्माण कार्यों में इज़ाफा हुआ। सड़कों पर वाहनों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसी के चलते शहर की खुद को ठंडा कर पाने की क्षमता में 12 से 21 प्रतिशत की कमी आई है। दिल्ली की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2011 में दिल्ली की जनसंख्या 1.38 करोड़ थी, जो अब 2.05 करोड़ आंकी गई है।

शहरों में बढती गर्मी में प्रबंधन करने के लिए हमें इससे जुड़े रुझानों को समझना होगा, इसमें गर्मी के तनाव को कम करने के लिए इमारतों के बेहतर डिजाइन और सामग्री का चयन भी शामिल है। दिल्ली को सिर्फ कागज़ों पर नहीं बल्कि ज़मीनी समाधानों की ज़रूरत है। जल स्रोतों और हरित क्षेत्र में भी इज़ाफा करने की ज़रूरत है। साथ ही वाहनों में कमी, बिल्डिंग के बेहतर निर्माण, वेंटिलेशन बिजली की खपत में गिरावट जैसे उपाय ज़रूरी है।

अनुमिता राय, चौधरी, कायकारी निर्देशक सीएसई

1980 से 2022 तक सबसे गर्म सालों का तापमान

1987	32.78 डि.से.
2002	32.14 डि.से.
2006	32.30 डि.से.
2009	32.35 डि.से.
2010	32.09 डि.से.
2016	32.38 डि.से.
2017	32.17 डि.से.
2018	32.20 डि.से.
2022	32.01 डि.से.

फ्लैट तैयार करते समय भी रखें यह ध्यानः शहर की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय मौसम को भी ध्यान में रखना जरूरी है। खिड़कियों को ओपन स्पेस की तरफ बनाना चाहिए। बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि फ्लैटों को ओपन स्पेस की तरफ खिड़कियां मिलें। खिड़कियों की साइज भो कमरों के अनुसार हो।

एम्स में धरातल पर नहीं उतरी किडनी के इलाज की सुविधा बढ़ाने की योजना

देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स में किडनी के इलाज की सुविधा बढ़ाने की योजना डेढ़ वर्ष में भी अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई। नई डायलिसिस मशीनें लगाने की योजना कागजों में ही सिमटी हुई हैं। इस वजह से एम्स का नेफ्रोलाजी विभाग 35 वर्षों से सिर्फ 13 डायलिसिस मशीनों के सहारे है। परिणाम स्वरूप ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचने वाले किडनी के मरीजों को एम्स में डायलिसिस की सुविधा भी नहीं मिल पाती। एम्स प्रशासन के अनुसार अब अगले वर्ष ही नई डायलिसिस मशीनें लग पाएंगी।

एम्स के नेफ्रोलाजी विभाग में 1989 में डायलिसिस की 13 मशीनें लगाई गई थीं। इसके बाद से अब तक डायलिसिस मशीनों की संख्या बढ़ नहीं पाई। जबकि एम्स में किडनी के मरीजों का दबाव बढ़ा है। मरीजों को ओपीडी में इलाज के लिए भी आसानी से अप्वाइंटमेंट नहीं मिल पाता। एम्स की ओपीडी में प्रतिदिन किडनी के करीब 200 मरीज देखे जाते हैं। मरीजों की तुलना में चिकित्सा संसाधन कम उपलब्ध होने से एम्स में किडनी मरीजों को नियमित डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल पाती है। इससे किडनी खराब होने की बीमारी से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को डायलिसिस के लिए परेशान होना पड़ता है। इस वजह से किडनी के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। नेफ्रोलाजी विभाग में एम्स प्रशासन ने अतिरिक्त बेड बढ़ाने व नई डायलिसिस मशीनें लगाने की मांग की थी। इसके मद्देनजर एम्स प्रशासन ने नवंबर 2022 में 15 नई डायलिसिस मशीनें लगाने का आदेश दिया था। साथ ही नेफ्रोलाजी विभाग के लिए 16 अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराने का फैसला किया था। 32 डायलिसिस मशीन खरीदने की चल रही है प्रक्रियाः एम्स के मीडिया डिविजन की प्रभारी डा. रीमा दादा ने कहा कि 32 डायलिसिस मशीनें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। टेंडर से संबंधित प्रक्रिया अंतिम चरण में है। टेंडर आवंटन के बाद नई डायलिसिस मशीनें आएंगी।

संपादकीय

शांति मिशन

वर्तमान सरकार आर.एस.एस. की योजनाओं को ही आगे बढ़ा रही है

आरएसएस 2025 में अपना शताब्दी समारोह मनाने की तैयारी कर रहा है, और हालांकि दबी जुबान में वह अभी इससे इनकार कर रहा है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली से परिचित लोगों के मुताबिक, अंदरखाने उसका शताब्दी समारोह की तैयारी बहुत ही शांति से चल रही है, जिसकी घोषणा के लिए उन्हें केवल संसदीय नतीजों का इंतजार करना होगा और अगर यह उनकी उम्मीदों के विपरीत हुआ तो उन्हें नए सिरे से योजना बनानी होगी, तब शायद उनके शताब्दी समारोह को थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जिस पैमाने पर वह जश्न मनाना चाहते हैं वह मौजूद नही है। इसे जारी रखने के लिए सरकारी नेतृत्व और संसाधनों की आवश्यकता होगी जो स्पष्ट रूप से केवल भाजपा सरकार में ही प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही देश के राष्ट्रपति ने भी उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता अधिनियम पर अपनी मुहर लगा दी है। ये दोनों क़ानून इस समय बहस का गर्म विषय हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुर्खियों में नहीं है तो धारा 370, राम मंदिर का निर्माण सीएए या यूसीसी जैसी समस्याओं के समाधान की जड़ है।

वर्तमान में संघ का कार्य जमीनी स्तर पर शाखाओं के माध्यम से होता है, लेकिन इसके कार्य का एक और पक्ष भी है जिसकी चर्चा भारतीय कार्य कारी मंडल की मार्च-अप्रैल बैठक में होती है। बैठक में होने वाली आम बैठक को सभा कहा जाता है और दूसरी बैठक अक्टूबर नवंबर में होती है आम प्रति निधि सभा की बैठक में देश भर से लगभग चौदह निर्वाचित कार्यकर्ता भाग लेते हैं, इस साल इसकी बैठक 15 मार्च को आयोजित की गई है। 16-17 दिनांक मार्च 2024, को नागपुर में। इन दोनों बैठकों में सिह देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इस संबंध में प्रस्ताव पारित किये जाते हैं। संघ की प्रतिनिधि सभा की पहली बैठक 1950 में हई थी और तब से लेकर अब तक देश की वर्तमान स्थिति और समस्याओं को लेकर 285 से अधिक प्रस्ताव पारित किये जा चुके हैं। इन प्रस्तावों की समीक्षा करने के बाद, यदि विषय या मुद्दे के आधार पर वर्गीकृत किया जाए, तो मोटे तौर पर मुख्य श्रेणियां हैं जिन पर किसी न किसी तरह से चर्चा की है।.. प्रस्ताव तो पारित हो गया होगा. संक्षेप में, श्रेणियां इस प्रकार हैं: महापुरुषों की वर्षगांठ, राष्ट्रीय मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पूर्वोत्तर भारत, असम, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गाय संरक्षण, शिक्षा, अल्पसंख्यक खुशनूदी, भारत की बँटवारा, धर्मपरिवर्तन रामजन्मभूमि संघ के संबंध में यदि हम उपरोक्त अनुभागों को ध्यान से देखें तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संघ की सोच और दूरदर्शिता का स्तर क्या होगा? यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से ऐसे विषय भी हो सकते हैं जो इन प्रस्तावों में शामिल नही हैं। यह संघ की राष्ट्रीय हित के मुद्दों के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। यहां यह कहना मुश्किल है कि भारत की गैर-भाजपा सरकारों ने संघ के लिए क्या किया है या किया है, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान सरकार संघ के प्रस्तावों को गंभीरता से लेती है। भाजपा के शासनकाल के दौरान भारत की संसद में प्रस्ताव सीएए और एनआरसी जैसे कानून पारित किए गए, राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और तत्काल मंदिर का निर्माण, वर्तमान सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करना, केंद्र प्रशासित राज्य जम्मू और कश्मीर को तीन क्षेत्रों में विभाजित करना कठोर धर्मांतरण कानूनों और गोहत्या विरोधी कानूनों के साथ, चीन और उन्हीं की भाषा में चुनौती पाकिस्तान की, बांग्लादेश की संघ के रुख के मुताबिक सीमा निर्धारण और सीमा विवाद के समाधान के साथ-साथ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मौजूदा सरकार काम कर रही है। दरअसल, संघ के ये सुझाव राष्ट्रीय संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छिपी भूमिका को समझने में मदद करते हैं। जैसा कि प्रस्ताव में देखा जा सकता है। संघ का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए ॠहदुओं को कानूनी प्रक्रिया के जरिए नागरिकता देना है। क्या आप जानते हैं इसकी जड़ें कहां हैं? इसकी जड़ें 1950 में पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हत्या, लूटपाट, आग, जबरन धर्म परिवर्तन, बलात्कार और अपहरण सहित कथित अत्याचारों पर पारित संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव में हैं, जिसमें कहा गया था कि विभाजन को स्वीकार करने के बावजूद मातृभूमि, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया गया है और न ही किया जा सकता है और इसलिए वे भारत से सभी सुरक्षा और सुरक्षा के हकदार हैं। संघ के इस प्रस्ताव को सीएए का आधार माना जा सकता है. 1986 में संघ ने समान नागरिक संहिता लागू की शाह बानो मामले में आवश्यकता के बारे में सरकार ने प्रतिगामी कदम नाम से एक प्रस्ताव पारित किया था। 1995 में संघ के कार्यकारी मंडल ने समान नागरिक संहिता नामक एक प्रस्ताव पारित किया। 1986 से 2021 तक इसके दोनों सत्रों में राम मंदिर या राम जन्मभूमि से संबंधित दस से अधिक प्रस्ताव पारित किए गए। 1961 से 2012 तक, संघ ने देश के पूर्वोत्तर राज्य असम और वहां कथित अवैध बांग्लादेशी कब्जे, हिंसा और अलगाववाद की देशव्यापी चुनौतियों जैसे मुद्दों पर अपने दो निकायों की बैठकों में नौ प्रस्ताव पारित किए हैं। संघ ने 1971 से 2021 तक बांग्लादेश और संबंधित राष्ट्रीय चुनौतियों पर तेरह प्रस्ताव पारित किए। समय-समय पर विध्वंसक ताकतें पंजाब में अपना खेल खेलने की साजिश रचती रहती हैं। संघ ने अकेले पंजाब राज्य के संबंध में 1982 से 1989 तक बारह प्रस्ताव पारित किये। ऐसे कई मुद्दे और विषय हैं जिन पर संघ हर साल अपने दो निकायों की बैठकों में प्रस्ताव पारित करते हैं। अपने संगठन एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से न केवल प्रस्ताव पारित होता है, बल्कि उस दिशा में भी असल में काम भी करता है। ये स्थिति ये बताने के लिए काफी है कि हमारे वर्तमान शासकों का क्या नजरिया है और उन्हें अल्पसंख्यक विरोध और मुस्लिम विरोध की खुराक़ कहां से मिल रही है।

तारीख़े इस्लाम

सिरतुन्नबी स.अ.स. पर लिखी गई सबसे तफ़्सीली किताब

अर-रहीक़ुल मख़्तूम

लेखक: मौलाना सफीउर्रहमान मुबारकपुरी किस्त 59

जहां तक श्बड़ की बकवासश के आरोप का ताल्लुक है, तो अल्लाह ने इसको रद्द करते हुए फरमाया, श्क्या तुम पैदाइश में ज़्यादा सख़्त हो या आसमान ?श और फरमाया, श्क्या यह नजर नहीं आता कि जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया और उनको पैदा करने से नहीं थका, वह इस पर भी कुदरत रखता है कि मुर्दों को जिंदा कर दे ? क्यों नहीं ? यक़ीनी तौर पर वह हर चीज पर कुदरत रखता है? साथ ही फरमाया, श्तुम पहली पैदाइश तो जानते ही हो, फिर हक़ीक़त क्यों नहीं मानते ?श अल्लाह ने वह बात भी याद दिलाई जो अक़ूल के पहलू से भी और चलन के पहलू से भी जानी-पहचानी है कि किसी चीज को दोबारा करना पहली बार करने से ज़्यादा आसान होता है। फरमाया, श्जैसे हमने पहली बार पैदा करने की शुरुआत की थी, उसी तरह पलटा भी लेंगे ।श और फरमाया, क्या पहली बार पैदा करने से हम थक गए हैं?

यों अल्लाह ने उनके एक-एक सन्देह का बड़े ही सन्तोषजनक ढंग से जवाब दिया, जिससे हर सूझ-बूझ वाला आदमी सन्तुष्ट हो सकता है, लेकिन मक्का के विरोधी हंगामा पसंद करते थे, उनमें अहंकार था, वे जमीन में बड़े बनकर रहना चाहते थे और सृष्टि पर अपनी राय लागू करना चाहते थे, इसलिए अपनी सरकशी में भटकते रहे।

3. विरोध का तीसरा तरीक़ा

पहलों की घटनाओं और कहानियों से कुरआन का मुक़ाबला करना और लोगों के कुरआन सुनने का अवसर न मिलने देना ।

मुश्रिक अपने उपरोक्त सन्देहों को फैलाने के अलावा हर संभव तरीक़े से लोगों को कुरआन सुनने से दूर रखने की कोशिश भी करते थे, चुनांचे वे लोगों को ऐसी जगहों से भगाते और जब देखते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दावत व तब्लीग से उठा चाहते हैं या नमाज में कुरआन की तिलावत फरमा रहे हैं तो शोर करते और तालियां और सीटियां बजाते। अल्लाह फरमाता है, कुफ्फार ने कहा, यह कुरआन न सुनो और इसमें शोर मचाओ, ताकि तुम गालिब रहो। इस स्थिति का नतीजा यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उनके मज्मों और महिफलों के अन्दर पहली बार कुरआन तिलावत करने का मौक़ा पांचवें सन् नुबूवत के आखिर में मिल सका, वह भी इस तरह कि आपने अचानक खड़े होकर कुरआन की तिलावत शुरू कर दी और पहले किसी को इसका अन्दाजा न हो सका।

नज़्र बिन हारिस कुरैश के शैतानों में से एक शैतान था। वह हियरा गया। वहां बादशाहों की कहानियां और रुस्तम व स्फन्दयार के कघ्स्से सीखे, फिर वापस आया, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी जगह बैठकर अल्लाह की बातें करते और उसकी पकड़ से लोगों को डराते तो आपके बाद यह आदमी वहां पहुंच जाता और कहता कि अल्लाह की क़सम ! मुहम्मद सल्लद्र की बातें मुझसे बेहतर नहीं। इसके बाद वह फारस के बादशाहों और रुस्तम व स्फन्दयार की कहानियां सुनाता, फिर कहता, आखिर किस वजह से मुहम्मद की बात मुझसे बेहतर है ?

इब्ने अब्बास की एक रिवायत है कि नज़्र ने एक लौंडी खरीदी थी, जब वह किसी आदमी के बारे में सुनता कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ मायल है तो उस लौंडी के पास ले जाकर कहता कि इसे खिलाओ-पिलाओ और गाने सुनाओ। यह तुम्हारे लिए उससे बेहतर है जिसकी तरफ तुमको मुहम्मद बुलाते हैं। उसके बारे में अल्लाह का यह इर्शाद उतरा। लोग ऐसे हैं जो खेल की बात खरीदते हैं, ताकि अल्लाह की राह से भटका दें।

अत्याचार और दमन-चक्र

सन् 04 नुबूवत में इस्लामी दावत के सामने आने के बाद मुश्रिकों ने उसके खात्मे के लिए पिछली कार्रवाइयां धीरे-धीरे अंजाम दीं। महीनों इससे आगे क़दम नहीं बढ़ाया और जुल्म व ज़्यादती शुरू नहीं की, लेकिन जब देखा ये तरीक़े इस्लामी दावत को नाकाम बनाने में असरदार साबित नहीं हो रहे हैं तो आपसी मश्विरे से तै किया कि मुसलमानों को सजाएं दे-देकर उनको उनके दीन से बाज रखा जाए। इसके बाद हर सरदार ने अपने क़बीले के मातहत लोगों को, मुसलमान हो गए थे, सजाएं देनी शुरू कीं और हर मालिक अपने ईमान लाने वाले गुलामों पर टूट पड़ा और यह बात तो बिल्कुल स्वाभाविक थी कि दुमछल्ले और गुंडे अपने सरदारों के पीछे दौड़ें और उनकी मर्जी और ख़्वाहिशों के मुताबिक़ हरकत करें। चुनांचे मुसलमानों और ख़ास तौर से कमजोरों पर ऐसी-ऐसी मुसीबतें तोड़ी गईं और उन्हें ऐसी-ऐसी सजाएं दी गईं, जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल फट जाता है। नीचे केवल एक झलक दी जा रही है-

अबू जहल जब किसी प्रतिष्ठित और शक्तिशाली आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा-भला कहता, जलील व रुसवा करता और माल को बड़े घाटे से दोचार करने की धमकियां देता और अगर कोई कमजोर आदमी मुसलमान होता तो उसे खुद भी मारता और दूसरों को भी भड़का देता।

भाजपा की प्रत्येक नीति में समाहित बुलडोजर राज : जयराम रमेश

18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है, साथ ही कांग्रेस के रणनीतिकार जयराम रमेश, जो राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, उन से अनेक मुद्दों और विपक्ष की योजनाओं के बारे में बातचीत हुई प्रस्तुत है इस बातचीत के प्रमुख अंश :-

सवाल :- कोडिकुन्निल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर न बनाए जाने से कांग्रेस नाराज है। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। क्या आप इसे टकराव का संकेत मानते हैं?

जवाब :- मुझे लगता है कि यह बुलडोजर मानसिकता का ही एक हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि किरेन रिजिजू (संसदीय कार्य मंत्री के रूप में) की नियुक्ति, जिन्हें मैं जानता हूँ, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बढ़िया और एक अच्छे व्यक्तिगत मित्र हैं, विश्वास जगाते हैं कि संसद से निपटने का एक अलग तरीका होगा। और प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे ने निश्चित रूप से और

> विपक्ष यानि हमें सुना जाना चाहिए, विधेयकों पर बहस होनी चाहिए और आगे के विचार-विमर्श के लिए स्थायी समितियों को भेजा जाना चाहिए और इसी तरह आप तीन आपराधिक न्याय विधेयकों की तरह दोनों सदनों के 145 सांसदों को निलंबित करके आगे नहीं बढ़ सकते।

सबूत दिए हैं। सभी परंपराओं और परंपराओं के अनुसार, कोडिकुन्निल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था। इस पद के लिए केवल दो वैध दावेदार थे : कोडिकुन्निल सुरेश और दूसरे वीरेंद्र कुमार। और चूंकि श्री कुमार एक केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए, यह श्री सुरेश होना चाहिए था। मुझे लगता है कि यह वही बुलडोजर वाला तरीका होगा जो पिछले 10 वर्षों में उनका रहा है।

सवाल :- लेकिन अब इस लोकसभा में विपक्ष की संख्या काफी अलग है।

जवाब :- सौ फीसदी, विपक्ष इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और भारतीय दल इस बार ऐसा होने देंगे। यह मोदी शाह की बुलडोजर रणनीति का मानक तरीका नहीं हो सकता, एनडीए और इंडिया समूह लगभग बराबरी पर हैं। हमारे पास संख्या है और हम जानते हैं कि 2024 का जनादेश एक गैर-जैविक पीएम की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। यही राजनीतिक वास्तविकता है।

सवाल :- यह लगभग एक धमकी की तरह लगता है, जैसे कि कह रहे हों कि 'यदि आप हमारी मांगों से सहमत नहीं हैं तो हम सदन को चलने नहीं देंगे।'

जवाब :- नहीं, नहीं। विपक्ष यानि, हमें सुना जाना चाहिए, विधेयकों पर बहस होनी चाहिए और आगे के विचार-विमर्श के लिए स्थायी समितियों को भेजा जाना चाहिए और इसी तरह आप तीन आपराधिक न्याय विधेयकों की तरह दोनों सदनों के 145 सांसदों को निलंबित करके आगे नहीं बढ़ सकते।

सवाल :- गांधीजी और डॉ. अंबेडकर की मूर्तियों को स्थानांतरित करने का मामला लें। मूर्तियों पर एक समिति है और चित्र, जो 17वीं लोकसभा में गठित भी नहीं थे। सभी प्रतिमाओं को, बिना किसी परामर्श के, स्थानांतरित कर दिया गया है और उन्हें प्रेरणा स्थल नामक कोई भव्य नाम दिया गया है।

जवाब :- ये सभी संकेत हैं कि बुलडोजर की रणनीति, मेरा तरीका या श्री मोदी का राजमार्ग दृष्टिकोण और नितिन गडकरी का नहीं। यदि वे इसे जारी रखना चाहते हैं, तो अब उन्हें जवाबी बुलडोजर से सामना करना पड़ेगा।

सवाल :- इस संसद सत्र के लिए आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं..?

जवाब :- यह एक छोटा सत्र है क्योंकि पहले दो दिन शपथ ग्रहण होगा, तीसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा और चौथे दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। लेकिन बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। छम्म्ज राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, का पूरा मुद्दा बहुत जरूरी मुद्दा है। 1 जुलाई को संसद के पिछले सत्र में भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अपराध संहिता को बदलने के लिए जो तीन कानून बनाए गए थे, उन्हें पारित कर दिया गया।

सवाल :- ये तीनों कानून बेहद अलोकतांत्रिक और बेशर्मी से पारित किए गए। अगर सरकार विपक्ष को उपसभापति का पद नहीं देती है तो क्या इंडिया ब्लॉक स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने पर विचार करेगा?

जवाब:- ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हर बात पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

> ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हर बात पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। क्या होगा, यह इंडिया ग्रुप के नेताओं के बीच चर्चा और बातचीत का विषय होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, खड़गे, जो आम तौर पर नेताओं और फ्लोर नेताओं की बैठक का समन्वय करते रहे हैं आगे भी बैठक करेंगे उन्हीं के अनुसार आगे की रणनीति तय होगी।

क्या होगा, यह इंडिया ग्रुप के नेताओं के बीच चर्चा और बातचीत का विषय होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, खड़गे, जो आम तौर पर नेताओं और फ्लोर नेताओं की बैठक का समन्वय करते रहे हैं बैठक करेंगे। पिछले पांच सालों में 17वीं लोकसभा इतिहास की एकमात्र ऐसी लोकसभा थी जो बिना उपाध्यक्ष के काम कर रही थी। 15वीं लोकसभा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-2 के तहत, में करिया मुंडा, जो भाजपा से थे, इस पद पर थे। 16वीं लोकसभा में भी उपाध्यक्ष थे।

मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाजपा और श्री मोदी अपनी बुलडोजर रणनीति को जारी रखने के मूड में हैं। यह हमारे संकल्प और दृढ़ संकल्प को और मजबूत करता है कि हम इस बार 16वीं और 17वीं लोकसभा की तुलना में कहीं अधिक मजबूती से उनका सामना करेंगे।

सवाल :- लेकिन आमतौर पर परंपरा यह है कि विपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हैं।

जवाब :- मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इस पर निर्णय हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सांसदों की भावना बहुत स्पष्ट है। भारतीय दलों की भावना भी बहुत स्पष्ट है, अगर आप 19 जून को श्री गांधी के 54वें जन्मदिन पर उनके द्वारा की गई गर्मजोशी और स्वागत को देखें। तो, हाँ पार्टी के सांसदों, नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और मुझे यकीन है कि श्री गांधी इन सभी कारकों पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही कोई निर्णय लेंगे।

स्माग टॉवर शहर की वायु गुणवत्ता को सुधारने में नहीं कर सकते हैं मदद : विभा धवन

सवाल :-इस बार की गर्मियां गर्म ही नहीं, प्रदूषित भी काफी है, क्यों ?

जवाब :-वैश्विक स्तर पर हर दशक पिछले दशक से अधिक गर्म रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी तापमान में वृद्धि का कारण बन रही है। भारत के संदर्भ में ये वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में इसलिए महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि हम पहले से ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च तापमान का अनुभव करते हैं। तापमान में कोई भी वृद्धि इसे और असहनीय बना देती है। वायु प्रदूषण सालभर की समस्या बन गया है, क्योंकि इसके अधिकांश स्रोत भी हमेशा बने रहते हैं।

सवाल :-जलवायु परिवर्तन का इस सब पर कितना असर कहा जा सकता है?

जवाब :- तापमान में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन के असर से अलग नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर इसके कारण भी तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर वर्षा, आर्द्रता और वाष्पीकरण पर पड़ रहा है।

सवाल :-दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यही सबसे उपेक्षित है ?

जवाब :- हर साल 65 प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली के बाहर स्थित स्रोतों से आता है, जो मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होता है। इससे निपटने के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। डीजल का उपयोग, निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित करना, प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना आदि अल्पकालिक उपाय हैं। हरित ऊर्जा (सौर उद्योग आदि) का उपयोग करके दीर्घकालिक सुधार लाए जा सकते हैं। ग्रीनहाउस गैसों को कैप्चर करना एक संभव दृष्टिकोण है। इसी तरह निर्माण स्थलों पर यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानदंडों की आवश्यकता है कि धूल स्थलों पर ही बैठ जाए। अधिक पौधे लगाने और डीजल जनरेटर से गैस जनरेटर में शिफ्ट करने से और भी कमी आएगी। यदि सफल होता है, तो यह सुधार गर्मियों के दौरान भी वायु गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। योजनाओं की व्यापक पहुंच और प्रसार की आवश्यकता है। योजनाओं को सरल रूपों और प्रारूपों में जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण बेहतर सार्वजनिक परिवहन के लिए नीति और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। हाइब्रिडध्इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग भी समय की मांग है।

सवाल :-दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों

> हर साल 65 प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली के बाहर स्थित स्रोतों से आता है, जो मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होता है। इससे निपटने के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। डीजल का उपयोग, निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित करना, प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना आदि अल्पकालिक उपाय हैं।

से आप कितनी सहमत और संतुष्ट हैं?

जवाब :-दिल्ली सरकार ने शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सराहनीय क़दम उठाए हैं। इन कदमों में सर्दियों के मौसम में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, स्वच्छ निर्माण दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन, कचरा संग्रहण में सुधार, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध शामिल हैं। हालांकि, इन नीतियों के मजबूत क्रियान्वयन, शहर में सड़कों के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और दीवार-से-दीवार पक्कीकरण की आवश्यकता है, ताकि धूल उड़ने को और कम किया जा सके।

सवाल :-स्माग टावर और रियल टाइम सोर्स अपार्शन्मेंट स्टडी या सुपरसाइट को लेकर आप क्या सोचती हैं?

जवाब :-स्माग टावर शहर की वायु गुणवत्ता को सुधारने में मदद नहीं कर सकते। समस्या को स्रोत पर ही कम करना होगा। वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन या सुपर साइट, महत्वपूर्ण कदम हैं, जो सरकार को समय पर वैज्ञानिक रूप से सूचित निर्णय लेने में मदद करेंगे।

सवाल :-सीएक्यूएम की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहेंगी?

जवाब :-सीएक्यूएम का ध्यान दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान पर केंद्रित है। मैं इस महत्वपूर्ण पहल की प्रारंभ से ही सदस्य रही हूं। इसने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संज्ञान लिया है, जैसे कि एनसीआर क्षेत्र में राज्यों के बीच उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के लिए दंड को मानकीकृत करना, धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए धूल सेल बनाना, थर्मल पावर प्लांट, स्वच्छ ईंधन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सार्वजनिक परिवहन, सड़क यातायात प्रबंधन, डीजल जनरेटर और पटाखों के विनियमन के लिए नीतियां विकसित करना।

सवाल :-टेरी विगत 50 वर्षों से पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करती आ रही है, नई पीढ़ी और आने वाले वर्षों के लिए टेरी का क्या विजन होगा।

जवाब :-टेरी पिछले 50 वर्षों से सतत विकास के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। यह जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाला पहला विकासशील देश का संस्थान है। पांच दशक पहले जे आर डी टाटा और दरबारी सेठ द्वारा इस संस्थान की स्थापना नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में और एक स्वस्थ ग्रह के विकास के लिए की गई थी। 1984 से डा. आर के पचौरी के गतिशील नेतृत्व में हमने सक्रिय अनुसंधान, नीति विकास और अनुसंधान को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने का काम किया। नई पीढ़ी को ग्रह के सीमित संसाधनों के बारे में जागरूक होना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी के साथ, नई पीढ़ी ऐसे नए रास्ते तय कर सकती है जो सभा के लिए और पृथ्वी के लिए एक स्थायी भविष्य विकसित करने में मदद करें।

मिज़ान

विराग गुप्ता

नीट जैसी धांधली रोकने के लिए कोचिंग माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो

एन.डी.ए. की गठबंधन सरकार को संसद के अधिवेशन में एन.टी.ए. विवाद पर कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया में मज़ाक चल रहा है कि यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें परीक्षा के आयोजक ही फेल हो गए हैं।

शुरूआत में सब कुछ पाक-साफ होने का दावा करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब 2 बड़ी गड़बड़ियों को मान लिया है। पहला, गलत पेपर और दूसरा ग़लत तरीके से ग्रेस मार्क देना लेकिन पेपर लीक के बारे में वे कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, जिसके बारे में एन.डी.ए. शासित गुजरात और बिहार की पुलिस जांच कर रही है।

गुजरात के गोधरा में पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। वहां पर 16 परीक्षार्थी संदेह के घेरे में हैं, जिनमें से 11 अन्य राज्यों के हैं। उसी तरीके से बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (ई.ओ.डब्ल्यू.) 11 छात्रों से पूछताछ कर रही है। मीडिया में मामला उजागर होने के बावजूद 27 दिन बाद भी एन.टी.ए. ने बिहार पुलिस को मूल प्रश्न पत्र नहीं भेजे हैं लेकिन नीट परीक्षा लेने वाली एन.टी.ए. गुजरात और बिहार की पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे रही। सरकार से सहयोग और जानकारी मिले तो आरोपियों के आपराधिक तंत्र का पर्दाफाश हो सकता है।

दो और बड़े सवाल हैं, पहला-रजिस्ट्रेशन की तारीख को रिओपन क्यों किया गया ? दूसरा-10 दिन पहले लोकसभा के चुनावों के रिजल्ट वाले दिन नीट के परिणाम क्यों घोषित किए गए ? आलोचकों के अनुसार लोकसभा के रिजल्ट के दिन के घालमेल से गड़बड़ी से जुड़े सभी विवादों को रफा-दफा करने की मंशा थी। मुख्य मुद्दों पर सरकार की चुप्पी और सही जवाब नहीं मिलने से बड़े पैमाने पर फेक न्यूज के प्रसार से एन.टी.ए. की छवि और दाग़दार हो रही क है। करोड़ों बच्चों के भविष्य का निर्धारण करने वाले ना नीट को सुध ारने का एक्शन प्लान अब ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता।

कोचिंग माफिया की भूमिका : कुछ दिनों पहले सरकार ने नया नियम लागू करने की मंशा जाहिर की थी, जिसके अनुसार कोचिंग में 18 साल से कम उम्र के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। सरकारी सूत्रों से प्रसारित ख़बरों के अनुसार विवाद और विरोध प्रदर्शन के पीछे कोचिंग की ताकतवर लॉबी का भी हाथ हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि नीट में हो रही गड़बड़ियों के पीछे एन.टी.ए. के भ्रष्ट अफसरों और ताकतवर कोचिंग संस्थानों की भूमिका है, जिसे नजरअंदाज़ करना ख़तरनाक हो सकता है।

सी.बी.आई. जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका के अनुसार गुजरात के गोधरा में परीक्षा केन्द्र - को चुनने के लिए दूर-दराज के कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड आदि राज्यों में 26 छात्रों ने 10-10 लाख की घूस दी थी। इस मामले में अनेक टीचरों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 26 छात्रों की डिटेल मिली हैं। परीक्षा में पेपर लीक होना एक देशव्यापी मर्ज बन गया है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में यह देखा गया कि सी.बी.आई. जांच से भी आरोपियों के तंत्र का पूरा खुलासा नहीं होता। कांग्रेस के अनुसार परीक्षा केन्द्र और कोचिंग सेंटर के नैक्सस में 'पैसे दो पेपर लो' का खेल खेला जा रहा है। इस वजह से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

इस बारे में कांग्रेस और यू.पी.ए. की दूसरी पार्टियों को यह समझने की जरूरत है कि उनके राज्यों में भी पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। कानून और व्यवस्था और पुलिस राज्यों का विषय है। इसके बावजूद यू.पी.ए. शासित राज्य सरकारें कोचिंग सेंटर और सरकारी अधिकारियों का तंत्र तोड़ने में विफल रही हैं।

काऊंसलिंग में विलम्ब : परीक्षाओं को दोबारा करने की मांग का सरकार के साथ कई अभ्यर्थी समूह विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई की सुनवाई के पहले 6 जुलाई से काऊंसलिंग शुरू करने का क्या मकसद हो सकता है?

सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले ही काऊंसलिंग शुरू करना चाहती है तो मामले से जुड़े सभी आरोपों पर पारदर्शी जवाब और ठोस कार्रवाई होना ज़रूरी है। छोटे-छोटे मामलों में ई.डी. की जांच रिपोर्ट, पंचनामा और बयानों का विवरण सार्वजनिक हो जाता है। उसी तरीके से सरकार अगर कोशिश करे तो 8 जुलाई के पहले ही सभी दोषियों को चिन्हित करके उन्हें कठोर दंड दे सकती है।

दो महीने पहले से ही गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी थीं, लेकिन चुनावों में व्यस्त सरकारी अमले ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब सरकार और एन.टी.ए. के अधिकारी बोल रहे हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अमरीका में एक भाषण में कहा है कि जिन मामलों में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें कोर्ट के पाले में ठेलना अच्छा नहीं है। इससे अदालतों में पैंडेंसी बढ़ने के साथ संविधान में किए गए शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था का हनन भी होता है। अमरीका में राष्ट्रपति के लड़के को हथियार के मामले में फास्ट ट्राइल करके अदालत में सजा सुनाई गई लेकिन भारत में अन्य नेताओं के ख़िलाफ अदालत से सज़ा जल्द नहीं मिल पाती है।

नीट से जुड़े सभी मामलों में सरकार का जवाब, याचिकाकर्ताओं के प्रति जवाब, बहस और फैसले में लम्बा समय लग सकता है। अदालती कार्रवाई में ज़्यादा ज़ोर देने पर मामला डीरेल होने के साथ काऊंसलिंग में विलम्ब हो सकता है। नीट परीक्षा में 24 लाख लोग शामिल हुए थे, इसलिए सभी पी.आई.एल. में अनेक अंतर्विरोध और चुनौतियां हैं। अलग-अलग मांगों से जुड़े याचिकाकर्ताओं के वकीलों में सहयोग और समायोजन के अभाव की वजह से अदालत में मजबूत और एकीकृत तरीके से पक्ष रखना मुश्किल होता है।

सामान्यतः अपराध के मामलों में सरकार पीड़ित पक्ष का साथ देती है लेकिन नीट जैसे मामलों में सरकार को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आरोपियों का बचाव करना होता है। नीट की पहली बड़ी चुनौती में फेल या पास होने से युवाओं के मैरिट की मान्यता के साथ विकसित भारत के रोड मैप की सफलता का निर्धारण होगा।

> शुरूआत में सब कुछ पाक-साफ होने का दावा करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब 2 बड़ी गड़बड़ियों को मान लिया है। पहला, गलत पेपर और दूसरा ग़लत तरीके से ग्रेस मार्क देना लेकिन पेपर लीक के बारे में वे कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, जिसके बारे में एन.डी.ए. शासित गुजरात और बिहार की पुलिस जांच कर रही है, कई व्यक्तियों को तथ्यों के साथ पकड़ा गया है, कई अन्यों की तलाश जारी है, कुल मिलाकर गड़बड़ी इतनी बड़े पैमाने पर हुई है कि तथ्यों पहुंचने में समय लग रहा है।

रोज़गार

बढ़ रही है ग्रीन जॉब्स के कौशल की मांग

इसमें कोई शक नहीं कि पर्यावरण सम्मत कामकाज और तकनीकों से संबंधित कौशल की मांग वैश्विक स्तर पर बड़ी है। वहीं, वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के चलते भारत में भी ग्रीन जॉब्स में प्रशिक्षित लोगों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020-21 में भारत में 8.63 लाख लोगों को इस क्षेत्र से संबंधित नौकरियां मिली हैं, जिसके बाद भारत दुनिया के उन विकसित देशों की कतार में खड़ा हो गया है, जहां हरित रोजगार के मौके बीते कुछ सालों में सबसे ज़्यादा बने हैं।

क्या है ग्रीन जॉब्स

ग्रीन जॉब्स या हरित रोजगार एन्वायरन्मेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ईएसजी) सेक्टर का हिस्सा होती हैं। इनमें पर्यावरण, सामाजिक प्रभावों और प्रशासन को कलमेल में रखने वाले उन स्किल से संबंधित नौकरियां होती हैं, जिनसे पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। इसमें तीन तरह की नौकरियां आती हैं रिन्यूवल एनर्जी से संबंधित, जिसमें सोलर पीवी और सोलर थर्मल, एनर्जी स्टोरेज, बायोमास पावर जैसे काम आते हैं। वहीं एन्वायरन्मेंट फरिस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कार्बन सिक्स, वाटर मैनेजमेंट आदि आते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत हरित परिवहन, हरित ईंधन, ग्रीन बिल्डिग से संबंधित काम आते हैं।

इन सेक्टर्स में मौके अधिक

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के अनुसार निर्माण एवं इंजीनियरिंग सेक्टर के बाद अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे तेजी से ग्रीन जॉब की मांग बढ़ने का अनुमान है। देश में सोलर फोटोवोल्टेक वर्टिकल में सबसे अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। भारत में 2021 में 2.17 लाख सोलर फोटोवोल्टेक नौकरियों और 4. 14 लाख हाइड्रोपावर नौकरियों का सृजन हुआ था। इसके बाद विंड एनर्जी और हाइड्रोपावर आते हैं।

मांग में हैं ये प्रोफाइल

नौकरियों के एक ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार ग्रीन जॉब को लेकर पिछले कुछ दिनों में स्थायी भूमिकाओं के लिए पदों के विज्ञापनों में 45: की वृद्धि हुई है। मांग वाले प्रोफाइल में सस्टेनेबिलिटी मैनेजर, पर्यावरण सलाहकार, सोलर प्रोजेक्ट मैनेजर, विंड एनर्जी इंजीनियर, बायो फ्यूल प्रोसेस इंजीनियर, पीएसबी डिजाइन इंजीनियर, ई-वेस्ट मैनेजर, हाइड्रो प्रोजेक्ट मैनेजर, ईएसजी एनालिस्ट, सुरक्षा विशेषज्ञ, सोलर पैनल इंस्टॉलर, इलेक्ट्रिक पर्यावरण विज्ञान में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पर्यावरण इंजीनियरिंग में बीटेक एमटेक कर सकते हैं। यहां इस क्षेत्र में स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इस क्षेत्र में पेशेवरों को 10 से 25 लाख सालाना तो वहीं फ्रेशर्स को 3 से 5 लाख रुपये सालाना वेतन मिलता है।

ये 4 स्किल आएंगे काम

1. इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल : स्किल्स रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से संबंधित और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कौशल और शिक्षा आपको मौके दिलाएगी। जैसे इन दिनों इको बिल्डिंग की मांग हर जगह है। ये ऊर्जा का संरक्षण करने वाले भवन होते हैं। बीटेक युवा इससे संबंधित अपस्किलिंग कर सकते हैं।

2. साइंस स्किल: विज्ञान से संबंधित जानकारी और समझ लगातार बढ़ानी होगी। तभी आप आगे रिसर्च कर पाएंगे और ग्रीन जॉब से जुड़ी चीजों और काम को अच्छे से समझ पाएंगे।

3. ऑपरेशन मैनेजमेंट स्किल ग्रीन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सेल्स इंजीनियर, क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट, ट्रांसपोर्टेशन प्लानर्स जैसी भूमिकाओं की भी मांग बढ़ने लगी है। आप इनमें अपस्किलिंग कर सकते हैं।

4. कानून की जानकारी पर्यावरण विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं पर्यावरण से जुड़े नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

ये डिग्री बनाएंगी रास्ता

एन्वायरन्मेंटल इंजीनियरिंग डिग्री

एन्वायरन्मेंटल लॉ डिग्री

एन्वायरन्मेंटल साइंस डिग्री

बैचलर ऑफ एन्वायरन्मेंट मैनेजमेंट

बैचलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट

बैचलर ऑफ साइंस इन फोरेस्ट्री

जाते हैं

प्रवेश प्रक्रिया

क्षेत्र और स्किल पर निर्भर करेगा कि आपको प्रवेश का कौन सा रास्ता लेना होगा। जैसे पर्यावरण कानून के क्षेत्र में क्लैट परीक्षा से रास्ते खुलेंगे, इस क्षेत्र में एमबीए के लिए कैट या संस्थान की अपनी परीक्षा देनी होगी। सरकारी संस्थानों के अलावा कुछ निजी संस्थान मेरिट के आधार पर भी प्रवेश देते हैं।

प्रमुख संस्थान

दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, गोरखपुरय आईआईटी, बीएचयू, जेएनयू, दिल्लीय जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी), दिल्लीय एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा

अपस्किलिंग के लिए कोर्स

ऑनलाइन मंचों पर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के तकरीबन 250 से अधि ाक कोर्स निशुल्क उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट - कोर्सेरा

ग्लोबल एन्वायरन्मेंट मैनेजमेंट कोर्सेरा

एन्वायरन्मेंटल मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटीज - एडएक्स (सशुल्क)

रिसोर्स एफिशिएंसी-लिंक्डइन

सरकारी ऑनलाइन मंच स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स`बहर.पद समय-समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करता है।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान nise-res-in

गुजरात सौर ऊर्जा संस्थान (जीआईएसई) gise-in मुख्य रूप से सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।

इस्लामी दुनिया

इमरान को हिरासत में लेने का फैसला गैरक़ानूनी

संयुक्त राष्ट्र के मनमाने हिरासत पर डार किंग ग्रुप का कहना है कि इमरान खान की हिरासत अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करता है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक, पूर्व संघीय राज्य मंत्री जुल्फी बुखारी लॉ फर्म द्वारा इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका पर कार्रवाई का विवरण अब 25 मार्च, 2024 की तारीख के साथ सामने आया है। जिसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार-डार किंग ग्रुप ने तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान की नजरबंदी से इनकार कियाहै।

उत्तरी सीरिया और इराक में ऑपरेशन के दौरान 13 आतंकवादी मारे गए

उत्तरी इराक और सीरिया पीकेके के 13 आतंकवादियों को मार गिराया। तुर्की सशस्त्र बलों का सफल संचालन के नतीजतन आतंकियों का सफाया जारी है तुर्की रक्षा मामलों के अनुसार, उत्तरी इराक में चल रहे पंजा और पंजा कुंजी संचालन के दौरान 10 और उत्तरी सीरिया में ब्रांच ऑलिव ऑपरेशन का के दौरान आतंकवादियों का सफाया हुआ।

यमनी सेना ने इजराइल की ओर जा रहे 4 जहाजों को नष्ट कर दिया

सना : यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जायोनी सरकार के चार जहाजों पर मिसाइलों से हमला किया है। सीटास की एक रिपोर्ट के अनुसार, केसी सार्री ने कहा कि हमलों में कंटेनर जहाज एमएससी यूनिक, तेल टैंकर डेलोनिक्स और की सिल्वर और अमिनोल पॉइंट को निशाना बनाया गया, जो ब्रिटिश नौसेना का हिस्सा है। वे इसमें कहा गया है कि यमनी सशस्त्र बलों ने इन जहाजों पर हमला करने के लिए क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया।

नेतन्याहू युद्ध की समाप्ति की घोषणा को जीत के रूप में पेश करने के तरीके तलाश रहे

तेल अवीव : इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ गाजा युद्ध का अंतिम चरण नजदीक है। गाजा में हमास द्वारा सैकड़ों इजरायली सैनिकों की हत्या के कारण अंततः नेतन्याहू सरकार को गाजा युद्ध से हटने की योजना बनानी पड़ी। नेतन्याहू अपने लोगों के सामने जीत के रूप में कैसे पेश किया जाए ऐसे योजना बना रहे हैं, नेतन्याहू को गाजा युद्ध पर न केवल दुनिया भर से बल्कि इजराइल के भीतर से भी तीव्र दबाव का सामना करना पड़ रहा है । इजराइल की भयानक बमबारी में बच्चों समेत 38 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों और यहूदियों की शहादत पर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी है।

बदलाव से ही "बदलेगी तस्वीर"

सुरेश सेठ

देश के कर्णधारों की यह स्वीकार करना होगा कि उपलब्धियों के चमकते आंकड़ों से कहीं अधिक आम आदमी की समस्याओं का समाधान जरूरी है। ये समस्याएं हैं- हर काम योग्य व्यक्ति को उसके काम की गारंटी, देश के हर नागरिक को उचित सेहत की सुरक्षा और नई पीढ़ी को दी जाने वाली वह शिक्षा, जो उन्हें दुनिया की श्रम मंडियों में एक बिकने वाली वस्तु नहीं, बल्कि अपने ही देश में एक ऐसी शक्ति बनाए जिसकी सहायता से हम अपने देश में एक नए युग का सूजन कर सकें, जिसे कायाकल्प कहते हैं। आज तक इन समस्याओं के समाधान की जगह अगर उन्हें आंकड़ों से बहलाने की कोशिश की जाती रही है, तो उसी का नतीजा है यह मोहभंग की अवस्था, जो आज देश की आम जनता से आंखें मिलाकर खड़ी हो गई है और जिसने पूरे देश में यह भावना पैदा की है कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। अब इस युग में एक नई कार्यदीक्षा से ही बात बनेगी। चिंतन और कारगुजारी में एक नया तेवर लाने से ही बात बनेगी। आम आदमी ने आज एक नया सच सामने रख दिया है कि भाषणों, दावों, अधूरे आंकड़ों और लंबित परियोजनाओं से नहीं, प्रगति और विकास की विश्व रैंकिंग की सीढ़ियां चढ़ने से भी बात नहीं बनेगी।

दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले इस देश में काम करने योग्य युवकों की संख्या सर्वाधिक है और वे अपने लिए इज्जत की रोटी चाहते हैं। अनुकंपाओं और उदारता की राजनीति अब उनको दिलासा नहीं देती।

अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का वादा 2029 तक बढ़ाकर उन्हें भूख से न मरने देने की गारंटी तो दे दी, लेकिन न तो उसका प्रशासन आम लोगों की खुशहाली का जामिन बन सका और न ही उनकी सेहत सुरक्षा का आश्वासन दे सका। देश के कुपोषित नौजवान ही नहीं, नौनिहाल भी उचित पोषण न पाने के कारण एक ऐसी आबादी बन रहे हैं, जो जिंदा तो है, लेकिन सेहत के प्रतिमानों पर पूरा नहीं उतरती। यहां शिक्षा के माडल की बहुत बात होती है, लेकिन देश को डिजिटल बना देने और कृत्रिम मेधा के संसार में अपना झंडा गाड़ देने के बावजूद हमारे देश के अधिकांश युवा ऐसे हैं, जिनकी व्यावहारिक योग्यता स्नातक की डिग्रियां लेने के बाद भी प्राथमिक स्तर की है। नौजवान आज भी इन शिक्षा परिसरों में परंपरावादी कला और विज्ञान की डिग्रियों के लिए दौड़ लगाते हैं, जबकि जमाना उनसे कृत्रिम मेधा और रोबीट युग में उतरने के साथ डीपफेक के संकटों का मुकाबला करने की चुनौती देता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे की इस शिक्षा के साथ देश में सस्ते उपचार के माडलों के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन निजी चिकित्सा इतनी महंगी है कि उसमें अपने परिवार का भविष्य संकट में डालने की जगह लोग नीम हकीमों के उपचार को शिरोधार्य करके मौत को गले लगाना अधिक पसंद करते हैं।

सरकार ने तो कह दिया कि सत्तर वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी, लेकिन आयुष्मान योजना का अनुभव बताता है कि इसके पहले सीमित क्षेत्र में भी पांच लाख की आय तक के नागरिकों को उचित उपचार नहीं मिलता था। निजी चिकित्सा क्षेत्र ने सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र का साथ देने का वादा कभी निभाया नहीं और सार्वजनिक क्षेत्र में उचित दवाओं से लेकर डाक्टरों का अभाव मरीज़ों के रोगी हो जाने का दुर्भाग्य उद्घाटित करता रहा। कारण औसत आयु कम ही रही है कि न उचित कमाई है, भारत में इसी और न उचित चिकित्सा। अशिक्षा के अंधेरों में अपराध पलता है।

देश की आधी से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश की सकल घरेलू आय में उसका योगदान घटते-घटते पंद्रह फीसद क्यों हो गया ? हमने घोषणा तो की थी कि हम अपनी प्रगतिशील नीतियों और कृषि क्रांति के साथ कृषकों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन वह आज भी अपनी फसल की उचित कीमत के लिए तरसते हुए महाजनों और साहूकारों से समझौते करते नजर आते हैं। जो लोग कृषि से उखड़ कर महानगरों में अपना वैकल्पिक आर्थिक जीवन ढूंढ़ने के लिए आए, उन्हें यहां कोई आधार नहीं मिला। कोविड महामारी ने उन्हें फिर गांव की ओर लौटा दिया। अब नई चुनौती यह है कि इस श्रमबल को वैकल्पिक जीवन कैसे दिया जाए? यह वैकल्पिक जीवन कस्बों और गांवों में ही विनिवेश करने से संभव होगा। इसके लिए लघु और कुटीर इकाइयों का जाल पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में बिछ जाना चाहिए, जहां कार्ययोग्य नौजवानों को उचित नौकरियां मिल सकें। उनका कमाया हुआ वेतन उन्हें वह आत्मसम्मान देगा, जिससे वे नए भारत के निर्माण में पूरे सम्मान के साथ जुड़ सकें।

> देश का सम्मान बढ़ाने के लिए देश को आयात आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा। इसे बनाने के लिए अपने रुपए का विनिमय महत्त्व भी डालर, पाउंड और यूरी के बराबर करना होगा। पिछले कुछ समय से मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत रुपयों के भुगतान से आयात और निर्यात करने का फैसला किया जा रहा है। यह भी फैसला किया गया है कि हमारे निवेशकों को अपने रुपए से विदेशों में निवेश करने की इजाज़त होगी।

देश का सम्मान बढ़ाने के लिए देश को आयात आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा। इसे बनाने के लिए अपने रुपए का विनिमय महत्त्व भी डालर, पाउंड और यूरी के बराबर करना होगा। पिछले कुछ समय से मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत रुपयों के भुगतान से आयात और निर्यात करने का फैसला किया जा रहा है। यह भी फैसला किया गया है कि हमारे निवेशकों को अपने रुपए से विदेशों में निवेश करने की इजाजत होगी। बड़ी दुनिया के देश अगर ऐसे मुक्त व्यापार समझौते हमारे देश के साथ नहीं करते, तो तीसरी दुनिया के अपने जैसे देशों में तो रुपए की पूरी परिवर्तनशीलता पैदा की जा सकती है। आरबीआइ ने इस सच को स्वीकार कर लिया है। देश के केंद्रीय बैंक ने दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के एजेंडे में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता रखा है। यानी भारतीय रुपए को विदेश भेजने से या विदेशी मुद्रा को देश में लाने की कोई रोकटोक नहीं होगी।

दूसरी मुद्राओं के सापेक्ष रुपाए की कीमत बाजार के तत्त्व तय करेंगे और उसको तय करेगा हमारे निर्यात का प्रोत्साहन। हम अपने देश की दस्तकारी और कला-कौशल की मांग पूरी दुनिया में पैदा करें, रुपया अपने आप मज़बूत होगा, कमज़ोर होने से बचेगा। सरकार

अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस विस चुनावों की तैयारियों में जुटी

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें पिछली बार के मुकाबले दोगुनी कर ली हैं। इससे उत्साहित पार्टी अगले तीन माह में होने वाले राज्यों की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर तैयारी की जा रही है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में युवा वर्ग पार्टी से जुड़ा है और इसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में भी मिलने जा रहा है। इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अग्निवीर योजना को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है क्योंकि चुनावी राज्यों जुड़े युवा इस योजना को लेकर काफी परेशान हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि युवाओं में केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर नाराज़गी है और उका रूझान कांग्रेस की तरफ है, इसलिए यह मुद्दा आने वाले स्थानीय विधानसभा चुनाव में पार्टी जोरशोर से उठाने जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, उनमें सबसे अधिक वोट फीसद हरियाणा में रहा है। हरियाणा में सबसे अधिक युवा सेना की भर्ती के लिए तैयारियां करते हैं। इस बार हरियाणा 47.6 सबसे अधिक मत मिला और यहां पर कांग्रेस पार्टी के 19.7 फीसद वोट बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि यह 1984 के बाद सबसे ज्यादा मत मिला है। इसके अतिरिक्त यह असर कुछ खास सीट पर नहीं बल्कि सभी दस लोकसभा सीट पर देखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 90 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का मत फीसद बढ़ा है। ये स्पष्ट संकेत है कि हरियाणा में बदलाव निश्चित है। हरियाणा में तीन माह बाद चुनाव होगा और कांग्रेस जीत दर्ज करेगी।

राज्य चुनाव में गठबंधन नहीं : हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आया है। इस गठबंधन का लाभ सभी दलों को मिला है और कांग्रेस भी एक मजबूत पार्टी की बतौर उभरी है। कांग्रेस नेताओं कहा कहना है कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था और अब जब राज्यवार चुनाव होंगे, तो सभी दल अपने अपने बूते पर लड़ेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी इसकी तैयारियों में जुट गई है। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही खत्म हो गया है।

हालांकि पार्टी के अंदर चल रही खटपट पर नेताओं ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि स्थानीय चुनाव में पार्टी के सभी नेता एक साथ चुनाव मैदान में खड़े नजर आएंगे।

चार राज्यों में होंगे चुनाव तैयारियां शुरू : जल्द ही चार राज्यों में चुनावी बिगुल बजेगा। इन राज्यों में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य शामिल है। इन राज्यों के लिए जल्द ही चार दिन का मंथन होगा।

इस मंथन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य शर्शीष नेता मौजूद रहेंगे। तय योजना के मुताबिक चार दिन इन राज्यों के वरिष्ट नेताओं के साथ मंथन होगा। तय रणनीति के मुताबिक 24 जून को झारखंड, 25 जून को महाराष्ट्र, 26 जून को हरियाणा और 27 जून को जम्मू कश्मीर की रणनीति पर कांग्रेस की बैठक होगी।

कुदरत के साथ बिगड़ता संतुलन

अब तो प्रकृति का बदलता स्वभाव सबको साफ समझ आने लगा है। हालांकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, लेकिन यकीनन किस्से, कहानियों-सी लगती है, जब गांवों में खपरैल के कच्चे मकान होते थे और चारपाई पर घरों के बाहर गहरी और बेफिक्र नींद सोते थे। न मच्छर का डर न बजबजाती नालियों की बदबू। मगर दो-तीन दशक में ही सब कुछ तेजी से बदल गया। विकास के नाम पर बड़ी-बड़ी बहुमंजिला इमारतें, घरों की पतली सीमेंट की दीवारें और इनके जल्द ठंडे या गर्म होने से कमरों के अंदर का हर दिन बदलता तापमान । तपते आंगन, तलवे जलाती कंक्रीट की सड़कें और घरों के सामने बजबजाती नालियां, भिनभिनाते मच्छर- मक्खियां। इस विकास के नाम पर बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर में पहुंच कर हम इतराएं, घबराएं या सिर धुनें?

मगर विडंबना है कि सारा कुछ जलवायु परिवर्तन के सिर पर मद कर बेफिक्री की चादर ओढ़े एसी, कूलर और मच्छरदानी के अंदर कैद होकर भी नहीं समझ पा रह हैं कि प्रकृति के जिस बदलाव को हमने देखा है, यह किसकी देन है? संकट में कौन है, पृथ्वी, आसमान, पाताल, इंसान या सभी ? पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इसका असर जलवायु पर कितने व्यापक तरीके से पड़ रहा है, सब सामने है। हर वर्ष बदलता मौसम, समुद्र का बढ़ता स्तर, बर्फ का लगातार पिघलना, लू, भारी बारिश, आंधी, तूफान, तड़ित झंझा और दावानल, जिसमें पहाड़ों के जंगल धधक उठते हैं। लगता है कि प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ गई है। मगर हम यह क्यों नहीं विचारते कि ऐसा क्यों है? आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि तपिश जिसे 'ग्लोबल वार्मिंग' कहते हैं, पूरी तरह मानव जनित है।

पृथ्वी पर ग्रीनहाउस गैसें ही गर्मी को रोकने वाली गैसों का एक प्रकृति प्रदत्त आवरण है। इसकी तुलना उस कंबल से की जा सकती है, जो पृथ्वी को उतना ही गर्म रखती है जितनी ज़रूरत है। मगर जब यही दूषित हो जाएंगी तो संतुलन तो बिगड़ेगा ही। ग्रीन हाउस गैसों के संतुलन का यह आवरण जितना डगमगाएगा या दूषित होगा, ग्लेशियर भी उतने ही पिघलते जाएंगे, जो अब अक्सर दिखने लगा है। जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैसा पहले नहीं था। आज तो साफ-साफ दिखने लगा है कि इससे हमारे भोजन, पानी तक की पूरी व्यवस्था प्रभावित है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड़ रहा है। शहर के शहर चंद हफ्तों के लिए 'गैस चौंबर' में बदल जाते हैं। हमारी यह प्रवृत्ति पारिस्थितिक तंत्र के साथ हमारी मानव प्रणालियों के पतन का कारण भी बनेंगी। लेकिन हम हैं कि निश्चित बैठे हैं।

ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चले ? हम अपनी भावी पीढ़ी के साथ भी यह अपराध कर रहे हैं। जन्मे अजन्मे और गर्भस्थ संतानों को तो पता भी नहीं है कि वह हमारे प्रकृति विरुद्ध अपराध के वातावरण में इस धरती पर हैं या होंगे और बेकसूर होकर भी भुगतेंगे। केवल मानव नहीं, जानवर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका क्या कसूर ? उन्होंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी सजा भुगत रहे हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में, बर्फ पर रहने वाले ध्रुवीय भालू अब बर्फ पिघलने के कारण जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही अनेक पशु-पक्षी, वनस्पतियां संघर्ष कर रही हैं, जो अलग-अलग पारिस्थितिक तंत्र में अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। सभी का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। तापमान और नमी में लगातार बदलाव के कारण कुछ प्रजातियां रहने के लिए नए स्थानों की तलाश में पलायन कर रही हैं, तो कई के वंश भी नष्ट हो जाते हैं। कई बदले वातावरण में जिंदा नहीं रह पाते हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई भी जीव या वनस्पति कहीं भी समायोजित हो जाए। अभी चंद हफ्तों पहले संयुक्त अरब अमीरात की चकाचौंध को बाढ़ में डूबते दुनिया ने देखा, जब शहर दुबई जबर्दस्त बारिश की चपेट में था। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में केवल चौबीस घंटे की लगातार बारिश ने ही लोगों को प्रकृति के साथ छेड़खानी का मजा चखा दिया। दरअसल, यह बारिश कोई प्राकृतिक नहीं थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि 'क्लाउड सीडिंग' का दुष्परिणाम है, तो कुछ जलवायु परिवर्तन के चलते बताते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन यह यह प्रकृति विरुद्ध कृत्य का ही नतीजा है। संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानी इलाकों का पारिस्थितिक तंत्र बीते बीस वर्षों में काफी बिगड़ गया है। यहां पर बहुतायत में रेत के भूरे टीले होते थे, जहां बारिश का पानी जमा होता था। बड़े-बड़े रिहाइशी और व्यावसायिक इमारतें बनाने के चक्कर में इन टीलों को खत्म किया जा रहा है और शहर में नए कृत्रिम हरित क्षेत्र बन रहे हैं, जिससे रेगिस्तान का पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरह गड़बड़ा गया है।

> जलवायु परिवर्तन के सिर पर मद कर बेफिक्री की चादर ओढ़े एसी, कूलर और मच्छरदानी के अंदर कैद होकर भी नहीं समझ पा रह हैं कि प्रकृति के जिस बदलाव को हमने देखा है, यह किसकी देन है? संकट में कौन है, पृथ्वी, आसमान, पाताल, इंसान या सभी ? पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इसका असर जलवायु पर कितने व्यापक तरीके से पड़ रहा है, सब सामने है। हर वर्ष बदलता मौसम, समुद्र का बढ़ता स्तर, बर्फ का लगातार पिघलना, लू, भारी बारिश, आंधी, तूफान, तड़ित झंझा और दावानल, जिसमें पहाड़ों के जंगल धधक उठते हैं। लगता है कि प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ गई है। मगर हम यह क्यों नहीं विचारते कि ऐसा क्यों है?

प्रकृति के प्रकोप की भारत में भी न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी और लगातार हो रही हैं। पूर्वोत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, तो पश्चिम में लंबी तटरेखा से घिरे हमारे देश का लगभग पूरा भौगोलिक क्षेत्र किसी न किसी प्रकार के जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। यह भी सच है कि अस्सी फीसद से अधिक लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जो जलवायु परिवर्तन से उपजी आपदाओं से हर समय घिरे रहते हैं। बारिश का बदलता ढर्रा, बढ़ता तापमान, भूजल में गिरावट, तेज चक्रवात, पिघलते ग्लेशियर, समुद्र का बढ़ता दायरा भविष्य में आजीविका के लिए बड़े संकट के रूप में मुंह बाए खड़ा है। यह न केवल हमरी खाद्यान्न व्यवस्था, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है।

आज भले शहर और गांव की आबादी को अलग-अलग देखा जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि शहरी आबादी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में सबसे ज्यादा है। आधुनिक कहे जाने वाले शहर और महानगरों की पोल पहली ही बारिश में खुल जाती है। लगता नहीं कि यह सब अनियंत्रित तथाकथित विकास की देन है, जो विनाश को निमंत्रण है। नदियों का रात-दिन छलनी होता सीना, अनवरत जारी प्राकृतिक संपदाओं का उत्खनन, बिना भूजल संरक्षण के केवल जल दोहन, गिट्टी और मुरुम के टूटते पहाड़, जंगलों की बेख़ौफ कटाई, वाहनों, कल-कारखानों से निकलता जहरीला धुंआ, पर्यावरण विरोधी गैसों का बेरोकटोक उत्सर्जन घातक हो रहा है।

मानवीय गतिविधियों से बिगड़ते जलवायु संतुलन और पारिस्थितिक तंत्र को तत्काल गंभीरता से लेना होगा। हर किसी को अपने-अपने प्रयासों से ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा, वरना देर हो जाएगी। भविष्य के विनाश की पटकथा लिखकर विकास की झांकी सजाना कितना उचित है? बस गांव, शहर, जंगल और पहाड़ के वातावरण को महसूस कर, करीब से समझ जान कर जो ज्यादा अच्छा लगे उसे अपने घर, आंगन में उतारने की हरेक की ईमानदार कोलिश ही पर्यावरण और 'ग्लोबिंग वार्मिंग' के लिए एक अच्छी पहल और भावी पीढ़ी के लिए चरदान हो सकती है।

लोस के बाद तीन विधानसभा सीट के उपचुनाव बने सुक्खू के लिए चुनौती

अभी लोकसभा के आम चुनावों की अस्सी दिन चली लंबी प्रक्रिया से सरकारी मशीनरी व राजनीतिक दल पूरी तरह निपटे भी नहीं थे कि प्रदेश में तीन और विधानसभा सीटों की रणभेरी बज गई। राज्यसभा की सीट के लिए हुए उपचुनाव में हुई क्रास वोटिंग का जो राजनीतिक हंगामा फरवरी महीने में हुआ था उसका असर अभी भी जारी हैं।

लोकसभा की चार सीटों के साथ साथ उन छह कांग्रेसी विधायकों के क्षेत्रों में भी उपचुनाव हुए जिन्होंने भाजपा के पक्ष में क्रास वोटिंग करके कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया था। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी छह कांग्रेसी विधायकों, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे, को अयोग्य करार दे दिया था। इन छह विधायकों में से दो बड़सर से इंद्रदत लखनपाल व धर्मशाला से सुधीर शर्मा ही भाजपा के टिकट पर जीत कर गए जबकि लाहुल स्पीति से रवि ठाकुर, गगरेट से चौतन्य शर्मा, कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो व सुजानपुर से राजेंद्र राणा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए हार गए। दूसरी ओर प्रदेश विधानसभा में जो तीन निर्दलीय विधायक देहरा से होशियार सिंह राणा, नालागढ़ से के एल ठाकुर व हमीरपुर आशीष शर्मा थे, इनके इस्तीफों पर विधानसभा अध्यक्ष ने तब फैसला दिया जब लोकसभा व छह विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो गया। ऐसे में अब ये तीन सीटें फिर से खाली हो गईं जिन पर अब 10 जुलाई को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इन तीनों ही निर्दलीय रहे विधायकों को अपना उम्मीदवार बना दिया है जबकि कांग्रेस नालागढ़ व हमीरपुर से 2022 में रहे उम्मीदवारों हरदीप सिंह बाबा व डा पुष्पेंद्र वर्मा पर ही दांव खेला है। देहरा से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से चुनावी रंग में है। एक बार फिर से भाजपा व कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी चारों सीटों पर हार मिली मगर उसके लिए हल्की राहत यह रही कि कुछ समय पहले उसके अपने ही विधायक रहे छह उम्मीदवारों के सामने नए चेहरे उतारने पड़े और इन पर चार में उसे जीत मिल गई। वर्तमान में 68 विधानसभा सीटों में से तीन खाली हैं जबकि 65 की संख्या में इस वक्त कांग्रेस के 38 व भाजपा के 27 विधायक हैं। अब तीन सीटों पर जंग शुरू हो चुकी है।

बाक़ी पेज 11 पर

ख़ास ख़बरें

ट्रंप मामला वापस निचली अदालत में

वाशिंगटन : अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमें से छूट के मामले को सुनवाई के लिए वापस निचली अदालत में भेज दिया है। इस कदम से ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन आपराधिक मामले में सुनवाई लंबी खिंच सकती है। इससे यह संभावना समाप्त हो गई कि पूर्व राष्ट्रपति घर नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले मुकदमा चलाया जा सकता है।

विजय माल्या के ख़िलाफ गैर ज़मानती वारंट

मुंबई : सीबीआई की विशेष अदालत ने भगौड़े उद्योगपति विजय माल्या के ख़िलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीबीआई अदालत के जज एसपी नाईक निंबालकर ने इंडियन ओवरसीज बैंक के 180 करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्ट मामले में 29 जून को वारंट जारी किया था। सीबीआई ने अदालत में अर्जी देते हुए कहा था कि ये गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए एकदम सटीक मामला है।

एचईसीएल के पूर्व सीएमडी पर केस दर्ज

सीबीआई ने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसीएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अविजीत घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि घोष पर रूस की एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के सहयोग से कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया गया है।

बुराड़ी जैसा मामला मध्य प्रदेश में भी सामने आया

अलीराजपुर/भोपालः साल 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में 11 लोगों के परिवार ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ऐसा ही हृदय विदारक मामला सोमवार को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सामने आया। यहा एक ही परिवार के पांच लोगों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।

सैम ऑस्ट्रेलिया की दूसरी महिला गवर्नर जनरल

मेलबर्न : ऑस्ट्रेलिया ने सैम मोस्टिन को अपना गर्वनर जनरल नियुक्त किया है। 123 वर्षों में इस पद पर नियुक्त होने वाली मोस्टिन दूसरी महिला हैं। यह, वर्ष 2022 में महाराजा चार्ल्स तृतीय का कार्यकाल शुरू होने के बाद से इस तरह की पहली ऑस्ट्रेलियाई नियुक्ति है।

मेलबर्न से दिल्ली आ रहे विमान में युवती की मौत

सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से दिल्ली आ रही एक भारतीय युवती की विमान में मौत हो गई। उसके साथ यह हादसा क्वांटास एयरलाइन के विमान में 20 जून को हुआ। हादसे की वजह तबीयत ख़राब होने की वजह से गिरना बताया जा रहा है।

इस्लामियात

मदारिसे इस्लामिया का उद्देश्य.....(1)

मदारिस इस्लामिया के क़याम का सिलसिला अहद नबूवत से जारी है, कुरआन व हदीस की तालीम हासिल करने के लिए सबसे पहले जिस जगह का इंतखाब किया गया था वह मस्जिद नबवी में वाकेअ एक मक़ाम है जिसे सफा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा अहादीस बयान करने वाले अज़ीम सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ि० इसी सफा के फैज़याफ्ता हैं तमाम दीनी मदारिस और कुरआन व हदीस की तालीम देने वाले इदारों की कड़ियां यहीं से जुड़ती हैं अलग-अलग ज़माने में इन इदारों की शक्लें विभिन्न रही हैं।

कभी लोगों ने एक जगह का इंतखाब करके वहां तालीम व तआलम का सिलसिला शुरू किया, कभी मस्जिद में दर्स का हलका लगाया गया, कभी किसी आलिम दीन के घर पर जाकर तशनगान उलूम ने अपनी तशनगी बुझाई कभी सरकार ने अपने प्रबंध वाले मदारिस क़ायम किए, कभी नवाबों और मालदारों ने दीनी तालीम के फरोग़ के लिए मदरसा क़ायम किया और सारे इख़्राजात की अदायगी ख़ुद की। 1857 के बाद संयुक्त हिन्दोस्तान को ऐसे हालात से दोचार होना पड़ा कि मदरसों की यह तमाम शक्लें ख़त्म हो गयीं दीनी तालीम की प्राप्ती और कुरआन व हदीस सीखने के लिए इन तमाम रास्तों का इख़्तयार करना बहुत मुश्किल हो गया। मुसलमानों की सत्ता का चिराग़ गुल हो गया मालदारों और नवाबों की ओर से मदारिस की स्थापना का रास्ता भी बन्द हो गया दूसरी ओर देश पर काबिज़ अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को उनके धर्म से दूर रखने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी, शआर इस्लाम से मुसलमानों को दूर करने की हर संभव कोशिश की, ऐसे मुकिश्ल तरीन हालात में हज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी और इनके साथियों ने कुरान व हदीस की तालीम जारी रखने के लिए एक नया रास्ता चुना। सरकार से कोई संबंध नहीं बनाए और किसी तरह का सहयोग लिए बग़ैर मदारिस के क़याम का सिलसिला शुरू किया, आम मुसलमानों के पैसे से आम मुसलमानों के बच्चों को कुरान हदीस की तालीम से आरास्ता करने की तहरीक चलायी, चन्दे पर आधारित एक नए निज़ाम का आगाज़ किया। उसूल हश्तगाना मुरत्तब करके यह हिदायत जारी कर दी कि कुरआन व हदीस की तालीम से हमकिनार करने की गरज़ से क़ायम मदरसों में न तो सरकार से कोई सहयोग लिया जाएगा न ही किसी शख़्स वाहिद (अकेले) के तआव्वुन के सहारे इरादा चलाया जाएगा और न ही नवाब और अमीर पर इन्हसार किया जाएगा बल्कि मिल्लते इस्लामिया के एक एक आदमी से एक-एक पैसा वसूल करके मिल्लत के बच्चों को मिल्ली दीनी और मज़हबी तालीम से आरास्ता किया जाएगा इसलिए किसी आलमे दीन और हाफिज़ कुरान से यह सवाल किया जाता है कि तुम्हें तालीम किसने दी है तो उसका जवाब होता है कि हमें मिल्लत ने तालीम सिखाई है मिल्लत के हम ऋणी हैं हमारी ज़िम्मेदारियां मिल्लत के लिए काम करने की हैं।

> मदारिस की स्थापना का रास्ता भी बन्द हो गया दूसरी ओर देश पर काबिज़ अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को उनके धर्म से दूर रखने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी, शआर इस्लाम से मुसलमानों को दूर करने की हर संभव कोशिश की, ऐसे मुकिश्ल तरीन हालात में हज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी और इनके साथियों ने कुरान व हदीस की तालीम जारी रखने के लिए एक नया रास्ता चुना।

इस तहरीक की पहली कड़ी दारुल उलूम देवबंद है चन्दे के निज़ाम पर आधारित वह पहला मदरसा है जिसके बाद यह सिलसिला शुरू होता है और महाद्वीप हिन्द व पाक में तमाम मुसलमानों ने धार्मिक शिक्षा के फरोग़ और शआयर इस्लाम की हिफाज़त के लिए इसी तर्ज़ पर मदरसे क़ायम करना शुरू कर दिया, किसी तफरीक के बग़ैर तमाम मसलकों से तआल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम और दर्दमंदाने मिल्लत ने इस तहरीक पर अमल करते हुए चन्दा करके मदरसे की बुनियाद डाली, इस्लामी तालीम के फरोग़ की उन्होंने फिक्र की, उन्होंने कदीम तालीमी निसाब को पेश नज़र रखते हुए एक निसाब तालीम मुरत्तब किया। कुरआन व हदीस और फिक्हा की तालीम को मरकज़ी मौज़ूं क़रार दिया, तमामतर तवज्जोह इन्हीं उलूम की प्राप्ती पर केन्द्रित की गयीं, हज़रत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी को सभी ने अपना इमाम तस्लीम किया। उलमा कराम ने अपने निसाब को आधुनिक शिक्षा से अलहदा इसलिए भी रखा कि हुकूमत की तरफ से आधुनिक शिक्षा सीखने का निज़ाम था, जगह जगह स्कूल व कॉलेजों को स्थापित किया जा रहा था जहां इस्लामी तालीमात के अलावा सारे कोर्सेज़ और विषयों को पढ़ाया जाता था, इसलिए मदरसों के उद्देश्यों में उलूम दीनिया को तरजीह दी गयी और इसी की मरकज़ी मौज़ूं क़रार दिया गया, रफ्ता-रफ्ता मदरसों ने भी ख़ुद को ज़माने से मिलाने की कोशिश की और ज़रूरत के अनुसार वहां भी असरी उलूम सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ, परिणामस्वरूप कुछ मदरसे तरक्क़ी करते हुए पूरी तरह मॉर्डन बन गए वहां का शिक्षा का पाठयक्रम बिल्कुल ही बदल दिया गया।

छुट्टियाँ और शिक्षा का समय भी यूनिवर्सिटी की तरह कर दिए गए, गरज़ व गाइयत भी बदल दी गयी, वहां के फुज्ला के बारे में यह इम्तियाज़ करना मुश्किल हो गया कि यह मदरसे के पढ़े लिखे हैं या किसी दूसरे इदारे के, कुछ मदरसों ने मामूली बदलाव किया, कुछ ने किसी तरह की तब्दीली के बग़ैर क़दीम निज़ाम को बरक़रार रखा और हर तरह के दबाव के बावजूद यह साफ ऐलान किया कि मार्डन शिक्षा की प्राप्ती के लिए सरकार की ओर से इदारे स्थापित किए गए हैं। धार्मिक शिक्षा का कोई नज़्म नहीं है इसलिए हम अपने निसाब तालीम से कोई समझौता नहीं करेंगे, कुरआन व हदीस का दर्स पूर्व की तरह जारी रहेगा, हाँ यहां से फरागत के बाद विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा सीखने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं।

यह दीनी मदरसे पिछले 15-20 वर्षों से लगातार सरकार और प्रशासन के निशाने पर हैं अनेक बार इन पर आतंकवाद की ट्रेनिंग देने के आरोप लगाए गए हैं सरकार ने इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश की है, मुसलमानों का एक वर्ग भी मदरसों के मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ है वह दीनी मदरसों में वही सब चाहते हैं जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में लागू हैं बहुत से बुद्धिजीवी मदरसों के निज़ाम तालीम को दकियानूसियत से ताबीर करते हैं।

शेष अगले अंक में.....

नूर-ए-क़ुरआन

सूरा आले इमरान नं. 03

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

आप कह दीजिए ए अल्लाह तमाम राज्यों के मालिक आप जिसको चाहें बादशाहत दे देते हैं और जिससे चाहे बादशाहत छीन लेते हैं और जिसको चाहें सम्मान दे देते हैं और जिसको चाहें अपमानित कर देते हैं प्रत्येक भलाई आपके हाथों में है निः संदेह आप प्रत्येक वस्तु पर अधिकार रखते हैं।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि नजरान के प्रतिनिधि मण्डल के अध्यक्ष अबु हारिस बिन अलकमा ने कहा था कि हम हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर ईमान लायें तो रूम का बादशाह जो हमारी मान-धन से सहायता करता है सब बन्द कर देगा। सम्भवतः यहां प्रार्थना के रंग में उसका उत्तर दिया गया है कि जिन बादशाहों की सल्तनत (राज्य) और उनके दिये हुए मान के लिए तुम रीझ रहे हो तो खूब समझ लो कि मान और राज्य का वास्तविक मालिक अल्लाह है। उसीके अधिकार और शक्ति में है जिस को चाहे दे और जिस से चाहे छीन ले। क्या यह सम्भव नहीं कि रूम और फारिस के राज्य और सम्मान छीन कर मुसलमानों को दे दी जाये, बल्कि वह वचनबद्ध है कि अवश्य दी जायेंगी। आज मुसलमानों का असहायपन और शत्रुओं की शक्ति को देखते हुए यह बात तुम्हारी समझ में नहीं जा सकती। इसीलिए यहूदी और मुनाफिक मज़ाक उड़ाते थे कि कुरैश के हमले से डर कर मदीने के चारों ओर खाई खोदने वाले मुसलमान रूम और फारिस के सम्राटों के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने का सपना देखते हैं, मगर अल्लाह ने कुछ ही दिनों पश्चात् दिखा दिया कि रूम और फारिस के जिन खज़ानों की कुंजिया उसने अपने रसूल के हाथों में दी थी। हज़रत उमर के समय में वे किस प्रकार इस्लाम के मुजाहिदों के बीच बांटे गये। वास्तविकता यह है कि यह सांसारिक मान और राज्य क्या वस्तु है, जब अल्लाह ने आत्मिक राज्य और सम्मान का अन्तिम स्थान (रसूल होने की पदवी) बनी इसराईल से बदल कर बनी-इसमाईल में पहुंचा दी तो रूम और दूसरे देशों के सांसारिक राज्यों का अरब के घुमक्कड़ों की ओर बदल देना क्या कठिन है।

अर्थात् यह दुआ एक प्रकार से भविष्यवाणी थी कि शीघ्र ही दुनिया की काया पलट होने वाली है। जो कौम दुनिया से अलग चलग पड़ी थी। यश और राज्यों की स्वामिनी होगी और जो शासन कर रहे थे उनको अपने बुरे कार्यों के कारण अपमान के गड्ढे में गिराया जायेगा।

आप रात को दिन में प्रवेश देते हैं और दिन को रात में प्रवेश देते हैं।

अर्थात कभी रात को घटा दिया और दिन को बढ़ा दिया। कभी इसके विपरीत करता है उदाहरणार्थ एक मौसम में 14 घन्टे की रात और दस घन्टे का दिन है। कुछ दिनों के पश्चात् रात के चार घन्टे काट कर दिन में जोड़ दिये जब रात दस घन्टे की रह गयी और दिन 14 घन्टे का हो गया। यह सब उलटफेर आपके हाथ में है क्योंकि चाँद सूरज और तारे आपकी इच्छा के बिना जरा भी हिल नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी के दिन बड़े कभी की रात यह अल्लाह की विचित्र रचना है।

और आप जानदार वस्तु को बेजान से निकालते हैं और बेजान वस्तु को जानदार से निकालते हैं।

अर्थात अण्डे को मुर्गी से और मुर्गों को अण्डे से, आदमी को वीर्य से और वीर्य को आदमी से, अनपढ़ को विद्वान से और विद्वान को अनपढ़ से, योग्य को अयोग्य से, अयोग्य को योग्य से निकालना आपकी ही कुदरत का काम है।

और आप जिस को चाहते हैं थे हिसाब रिज़्क़ देते हैं।

सल्ल. शाह अब्दुल कादिर साहब लिखते है-''यहूदी जानते थे कि पहले जो बढ़ाई हम में थी वही सदैव रहेगी। अल्लाह की कुदरत से आआंख बन्द किये है, जिसको चाहे सम्मान दे और राज्य दे और जिससे चाहे छीन ले और अपमानित कर दे और अज्ञानियों में से शानी पैदा कर दे जैसे अरब के अनपढ़ों में से बनाये और ज्ञानियों में से अज्ञानी जैसे बनी इसराईल में हुआ और जिसको चाहे प्रत्यक्ष व परोक्ष असीम रिज़्क़ दे।

मुसलमान ईमान वालों को छोड़कर सचाई का इनकार करने वालों को दोस्त न बनायें और जो कोई ऐसा करेगा तो उसको अल्लाह से कोई लगाव नहीं मगर इस हालत में कि तुमको उनसे अपना बचाव करना हो।

अर्थात जब राज्य और मौन प्रतिष्ठा और हर प्रकार की जलटा-पलटी और परिवर्तन की नकेल अल्लाह ही के हाथ में है तो मुसलमानों को जो वास्तविक अर्थों में उस पर ईमान रखते हैं उचित नहीं कि अपने इस्लामी भाइयों के भाईचारे पर बस न करके अल्लाह के शत्रुओं से दोस्ती करें और उधर पग बढ़ायें। अल्लाह और रसूल के शत्रु उनके मित्र नहीं हो सकते। जो इस जनर्च में पड़ेगा समझ लो अल्लाह के प्रेम और मित्रता से उसको कोई प्रयोजन नहीं। एक मुसलमान की जाशायें और भय केवल अल्लाह ही से सम्बिन्धित होने चाहिए। उसके प्यार और भरोसे के योग्य वही लोग हैं जो अल्लाह से इस प्रकार का सम्बन्ध रखते हैं। हाँ अच्छा व्यवहार न्याय, मेल मिलाप का व्यवहार और भली प्रकार मिलना ये वस्तुएं और गुण है जिनका मुसलमान को आदेश दिया गया है। उसका यह व्यवहार मुसलमान के साथ ही नहीं बल्कि इनकारियों के साथ भी आवश्यक है। हां जो वर्ग इस्लाम के प्रति शत्रुता और द्वेष का प्रदर्शन करें तो वहां दोस्ती इस्लाम के लिए हानिकारक है। इसके सम्बन्ध में सूरा. 60 के रुकू नं. 2 की प्रारम्भिक आयतों में देख लिया जाये। वहां इसके सम्बन्ध में इस्लाम का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से सामने आ जायेगा।

दक्षिण में भी पड़ा है एक से एक "पलटीमार"

एस. श्रीनिवासन

वैसे दक्षिण में एनडीए की मजबूती बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी को लगातार अपने कंधे पर नज़र रखनी पड़ेगी। वैसे तो बिहार के एक नेता के विरोधी उनके यू-टर्न के लिए उनको 'पलटू राम' कहते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू उन्हें भी मौक़ापरस्ती व सियासी कलाबाजी के कुछ गुर सिखा सकते हैं। अपने फैसले पलटने का काम नायडू ने अपने 46 साल के लंबे सियासी करियर में बखूबी किया है।

जब प्राथमिक विकल्प नाकाम हो जाता है, तब रणनीतिकार अक्सर आकस्मिक योजना का विकल्प चुनते हैं। इसी तरह लगातार चुनावी कामयाबी का लक्ष्य रखने वाले राजनेता अपनी मूल रणनीति को लागू करने में निहित जोखिमों से अच्छी तरह वाकिफ होते हुए सावधानी से 'बैकअप' योजनाएं तैयार करते हैं। मिसाल के लिए, जब नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाजपा के लिए 370 सीटें और एनडीए सहयोगियों की सहायता से 400 सीटें हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, तब उन्होंने संख्या बल में कमी की स्थिति में दक्षिणी राज्यों को अतिरिक्त समर्थन के संभावित स्रोत के रूप में देखा था। दक्षिण में सीटें जीतना उनकी वैकल्पिक योजना या प्लान-बी का हिस्सा था।

राजनीति में मूल योजना और द्वितीय योजना के नाकाम होने के बाद नेता तीसरी योजना का भी सहारा लेते देखे जाते हैं। हालांकि, यह तीसरी योजना ज्यादा मुकम्मल नहीं हो सकती। मिसाल के लिए, यदि चंद्रबाबू नायडू से फिर समर्थन लेने का मोदी का प्लान बी नाकाम हो जाता, तो उन्हें बचाव के लिए एक प्लान सी भी तैयार करना पड़ता। गौर करने की बात है कि अब तक मोदी अपने प्लान-बी को लागू कर खास फायदा लेने में कामयाब रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दक्षिण की कुल 130 लोकसभा सीटों में से 29 सीटें स्वतंत्र रूप से हासिल की थीं। इसके अलावा, भाजपा को एक अतिरिक्त सीट तब मिली, जब अभिनेता अंबरीश की पत्नी सुमलता, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जीत के बाद भाजपा में शामिल हो गईं।

लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा को दक्षिण से लगभग उतनी ही, 29, सीटें मिली हैं, जबकि वह एनडीए के साथ मिलकर 45 सीटें जीतने में कामयाब रही है। वैसे दक्षिण में एनडीए की मजबूती बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी को लगातार अपने कंधे पर नज़र रखनी पड़ेगी। वैसे तो बिहार के एक नेता के विरोधी उनके यू-टर्न के लिए उनको 'पलटू राम' कहते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू उन्हें भी मौक़ापरस्ती व सियासी कलाबाजी के कुछ गुर सिखा सकते हैं। अपने फैसले पलटने का काम नायडू ने अपने 46 साल के लंबे सियासी करियर में बखूबी किया है।

अब यह एक इतिहास है कि 28 वर्षीय नायडू ने अपने सियासी करियर का आगाज अविभाजित आंध्र प्रदेश में वाई राजशेखर रेड्डी के साथ युवा कांग्रेस नेता के रूप में किया था। दोनों नेता अच्छे दोस्त थे, पर उनकी सियासी किस्मत ने अलग-अलग राह पकड़ ली। 30 साल की उम्र में नायडू सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। वह एक वफादार कांग्रेसी बने रहे, हालांकि, उनकी शादी मशहूर अभिनेता एन टी रामा राव की बेटी से हुई। रामा राव ने कांग्रेस को हटाने के मकसद से तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। एक समय तो नायडू ने अपने ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई थी, पर जल्द ही उनकी हिचक. दूर हुई और कांग्रेस में गिरावटको भांपते हुए नायडू ने पलटवार.. किया और तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। लोग याद करते हैं कि साल 1999 में भी नायडू भाजपा के साथ मिल गए थे और रिकॉर्ड 29 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। इस जीत ने उन्हें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से ख़ास रियायतें लेने में सक्षम बना दिया था। वैसे साल 2004 और साल 2009 में वह कांग्रेस नेता राजशेखर रेड्डी के सामने टिक न सके। तब उन्होंने विपक्षी वोटों को बांटने के लिए सुपरस्टार चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी या पीआरपी को दोषी ठहराया था। साल 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तब उन्हें चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण द्वारा शुरू की गई जन सेना के साथ गठबंधन में कोई हिचक नहीं हुई। तब नायडू को मोदी की भाजपा से भी गठबंधन करने में कोई परेशानी नहीं हुई। उनके यू-टर्न ने ही उन्हें साल 2014 में सत्ता में लौटने में मदद की थी, पर नायडू का मन ज्यादा समय तक कहां स्थिर रहता है?

साल 2018 में भाजपा के साथ उनके रिश्ते में फिर कड़वाहट घुल गई और उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने में केंद्र की नाकामी के विरोध में तेदेपा के दो मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। और तो और, एक साल बाद ही 2019 में उन्होंने संसदीय चुनाव लड़ने के लिए दशकों से कट्टर दुश्मन रही कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, परहार गए। इसके बाद वह फिर एनडीए में लौटने के लिए संघर्ष करने लगे। मुख्यमंत्री जगनमोहन का शिकंजा कसता जा रहा था और कथित भ्रष्टाचारके एक मामले में उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। कभी रोते हुए नायडू ने प्रतिज्ञा की थी कि वह केवल मुख्यमंत्री के रूप में ही राज्य विधानसभा में लौटेंगे।

साल 2024 के चुनाव में उनकी गुहार पर जनता ने गौर किया। भाजपा ने जन सेना और तेदेपा के साथ गठबंधन में विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा चुनावों में भी भाग लिया और मिलकर 21 लोकसभा सीटें हांसिल की हैं। भाजपा को पहली बार राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जगनमोहन की पार्टी औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा नहीं है, फिर भी संसद में भाजपा का समर्थन कर रही है।

बहरहाल, चंद्रबाबू नायडू की तरह पवन कल्याण के भी स्वार्थ और अवसरवादिता से संचालित होने की बड़ी आशंका है। वह भी पलटते रहे हैं। उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत बड़े भाई चिरंजीवी के साथ की थी। मगर जब उनके बीच मतभेद सामने आए, तब जल्द ही उन्होंने रिश्ते तोड़ लिए। पवन कल्याण ने साल 2014 में जन सेना लॉन्च करके भाजपा का समर्थन किया, पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ गए। भारतीय जनता पार्टी पर दक्षिणी राज्यों के अधिकारों को कुचलने का आरोप भी लगा दिया। सियासी विडंबना देखिए, साल 2024 में उन्हें उसी भगवा दल के साथ गठबंधन करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

बेशक, आंध्र प्रदेश में सियासी खींचतान से वाकिफ भाजपा ने शायद अपना रास्ता तैयार कर लिया है, वह अपने गठबंधन में सहयोगियों को साथ लेकर खुद को मजबूत करने में जुटी है। गौर कीजिए, अमूमन राज्यों के सरकारी कक्षों में सिर्फ मुख्यमंत्री की तस्वीर दीवारों पर सजती है, पर आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ उनके उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण की भी तस्वीर सज रही है। क्या यह अपनी मोर्चाबंदी को टूटने से रोकने का चंद्रबाबू नायडू का नया तरीका है?

राहुल रायबरेली से वायनाड तक !

मौजूदा लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने अपना सफर केरल के वायनाड से लेकर उत्तर प्रदेश के रायबश्ली तक जिस तरह सफलतापूर्वक पूरा किया है उसने उनकी दादी स्व. इन्दिरा गांधी की याद ताजा कर दी है। 1980 में इन्दिरा जी ने भी दो सीटों रायबरेली व तत्कालीन आंध प्रदेश के मेहक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत दर्ज की थी। 2014 में प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी वाराणसी व बड़ौदा दो सीटों पर सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था। संभवतः राहुल गांधी एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्होंने दो सीटों पर चुनाव लड़ा। मगर संविधान के अनुसार उन्हें एक सीट खाली करनी होगी और उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है। वायनाड ने उनका बुरे वक्त में साथ दिया था और 2019 में उन्हें जिताकर लोकसभा में भेजा था जबकि वह उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट हार गये थे। अतः वायनाड के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती थी। इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी को वायनाड से उपचुनाव लड़ाने का फैसला किया है जिससे गांधी परिवार को ही वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रियंका गांधी की राजनीति की समझ बहुत परिपक्व है और वर्तमान चुनायों में कांग्रेस का ग्राफ ऊपर लाने में उनका योगदान भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस पार्टी भारत के दक्षिण से लेकर उत्तर तक में अकेली पार्टी होगी जिसमें केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक के लोगों का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व होगा हालांकि इस बार केरल से सत्तारूढ़ पार्टी का भी एक सांसद चुना गया है परन्तु केरल में कांग्रेस ने वामपंथी दलों का सूपड़ा सा साफ कर दिया है। यह भी एक तथ्यात्मक इतिहास है कि बुरे दिनों में दक्षिण के राज्यों ने कांग्रेस का साथ जमकर दिया है। 1977 में जब विपक्षी दलों की पंचमेल पार्टी जनता पार्टी का गठन हुआ था तो पूरे उत्तर भारत में इसकी लह चल पड़ी थी और इसे 298 सांसद मिले थे। मगर दक्षिण के राज्यों में इसे केवल एक सीट स्व. संजीव रेड्डी की आन्ध्र प्रदेश से मिली थी। वह भी बाद में राष्ट्रपति बन गये थे। दक्षिणी राज्यों व कुछ अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों से इन चुनावों में कांग्रेस को 153 सीटें मिली थीं।

लोकसभा में तब कांग्रेस ने अपना विपक्ष का नेता केरल से ही स्व. सी. एम. स्टीफन को चुना था। स्व. स्टीफन खुद ईसाई थे मगर हिन्दू धर्म ग्रन्थों का उनका अध्ययन इतना गहरा था कि लोकसभा में अपने वक्तव्यों से उन्होंने तत्कालीन जनता पार्टी नेताओं से भी लोहा मनवा लिया था। स्व, स्टीफन संस्कृत के भी विद्वान थे। गीता के श्लोक उन्हें कंठस्थ थे। कहने का मतलब यह है कि केरल राज्य परंपरागत रूप से कांग्रेस की विचारधारा का प्रवाहक माना जाता रहा है। श्रीमती प्रियंका गांधी ने भी इसी विचारधारा को 2024 के चुनावों में फैलाने में मदद की और रायबरेली व अमेठी दोनों चुनाव क्षेत्रों में उन्होंने मतदाताओं को यह बताने का भरपूर प्रयास किया कि भारत में लोक कल्याणकारी राज की स्थापना ही भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य है। इतने दुरूह विषय को उन्होंने जनता से सीधा संवाद करके समझाने का प्रयास किया जिसमें वह सफल रहीं। रायबरेली व अमेठी के अलावा प्रियंका ने देश के लगभग हर राज्य में चुनाव प्रचार भी किया और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि मौजूदा परिस्थितियों में इंडिया गठबन्धन ही सकारात्मक विकल्प है क्योंकि गांधी और नेहरू की विरासत की राजनीति करना इस गठबन्धन का धर्म बन चुका है। रायबरेली व अमेठी में डेरा डाल कर प्रियंका गांधी ने पूरे अवध क्षेत्र को इस प्रकार आन्दोलित किया कि पड़ोस की सुल्तानपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी उनकी चाची मेनका गांधी चुनाव हार गईं और अयोध्या (फैजाबाद) से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह भी परास्त हो गये। इनके अलावा पूर्वांचल की और भी अनेक सीटें इंडिया गठबन्धन जीत गया। प्रियंका नौजवान पीढ़ी की एक होनहार व शब्दों का शास्त्रीय चयन करने वाली सफलतम चुनाव प्रचारक हैं। वायनाड से यदि वह चुनाव लड़ रही हैं तो मतदान से पहले ही उनकी जीत के नतीजे पर भी पहुंचा जा सकता है मगर राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, अतः उन्हें वायनाड में भी पूरा दम-खम लगा कर चुनाव लड़ना होगा।

राहुल गांधी द्वारा रायबरेली सीट पर बना रहना गांधी परिवार की मजबूरी भी हो सकती है क्योंकि यह सीट उनके दादा स्व. फिरोज गांधी से लेकर उनकी दादी इन्दिरा गांधी व माताश्री सोनिया गांधी तक की रही हैं। पं. नेहरू ने तो 1920 के लगभग अपनी राजनीति की शुरूआत ही रायबरेली के गांवों से की थी। इस सन्दर्भ में 1945 में प्रकाशित एक पुस्तक 'कलेक्टेड स्पीचेज आफ जवाहर लाल नेहरू' बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें नेहरू जी द्वारा किसानों की सभाओं में दिये गये भाषण संग्रहित हैं। उस समय नेहरू जी ने रायबरेली के किसानों से आह्वान किया था कि वे रूढ़ीवादी परंपराएं छोड़ कर आगे बढ़ें और जात-पात को देखकर लोगों का मूल्यांकन करना बन्द करें। 2024 के चुनावों के दैरान प्रियंका गांधी की नुक्कड़ सभाओं के सन्देश को देखा जाये तो उन्होंने भी रायबरेली व अमेठी के लोगों से यही आह्वान किया कि वे सरकार के लोगों की जिम्मेदारी तय करते हुए जनता के प्रति जवाबदेह बनायें और उनसे उनके कामकाज का हिसाब-किताब मांगे। वह कहती थीं कि नेताओं की आदत मत खराब कीजिये और उनसे पिछले पांच साल का हिसाब मांगिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनिये। क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही लोकतन्त्र को मजबूत बना सकता है। उनकी बातों का असर इस कदर हुआ कि अमेठी से केन्द्रीय मन्त्री स्मृति इरानी कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से एक लाख 67 हजार वोटों से हार गई।

खेल जगत

कार्यक्रम को सहज बनाने में देवधर ट्रॉफी ग़ायब

भारत ने 20/20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीत लिया है और इसके बाद बीसीसीआई ने भारतीय युवा टीम में कुछ परिवर्तन करके अपने सालाना कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बीसीसीआइ ने घरेलू क्रिकेट सीजन 2024-25 के लिए कैलेंडर की घोषणा कर दी है। अपनी हर खास मुद्दे को देरी तक टालने की प्रतिष्ठा के उलट उसने पिछले सीजन के दौरान आई कई दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की है। 2023-24 में यदि क्रिकेटरों पर रणजी ट्राफी को नजरअंदाज़ करने का आरोप लगा तो मैचों के कार्यक्रम का मुद्दा भी कोई कम नहीं था।

कार्यक्रम को सहज, सरल और तनावरहित बनाने को कोशिश में बीसीसीआइ ने क्रिकेट कैलेंडर से देवधर ट्राफी को गायब कर दिया है। देवधर ट्राफी सीमित ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट है। अभी मुंबई में रणजी ट्राफी सेमी फाइनल खेले शार्दुल ठाकुर ने कहा था कि खिलाड़ियों के लिए लगातार 10 ऐसे मैच खेलना जो एक-दूसरे से तीन दिन बाद ही शुरू हो रहे हों, बड़ा मुश्किल है और बीसीसीआइ को इस पर सोचना चाहिए। जरूरत है लंबे अंतराल की। तमिलनाडु के कप्तान साई किशोर ने तो कहा कि मैचों के बीच, कम अंतराल तेज गेंदबाजों पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है और मैच से पहले अभ्यास के लिए समय ही नहीं है।

टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ भी इनसे सहमत थे और कहा- देश के लंबे घरेलू सीजन की सही समीक्षा की ज़रूरत है। एक लंबा रणजी सीजन और साथ में दलीप और देवधर ट्राफी को भी जोड़ दें तो .हालत तरस खाने वाली हो जाती है। पिछले साल, दलीप ट्राफी जून में खेले आइपीएल से लगभग एक महीने बाद। सच यह है कि सीजन के दौरान ऐसे खिलाड़ी ही सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं जो टीम इंडिया में आने के दावेदार हैं और संयोग से उन्हीं की टीमें सेमी फाइनल और

> अभी मुंबई में रणजी ट्राफी सेमी फाइनल खेले शार्दुल ठाकुर ने कहा था कि खिलाड़ियों के लिए लगातार 10 ऐसे मैच खेलना जो एक-दूसरे से तीन दिन बाद ही शुरू हो रहे हों, बड़ा मुश्किल है और बीसीसीआइ को इस पर सोचना चाहिए। जरूरत है लंबे अंतराल की। तमिलनाडु के कप्तान साई किशोर ने तो कहा कि मैचों के बीच, कम अंतराल तेज गेंदबाजों पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है और मैच से पहले अभ्यास के लिए समय ही नहीं है।

फाइनल खेलती रहती हैं। ये ही फिर टीम इंडिया और इंडिया ए टीम में आ जाते हैं। ऐसे क्रिकेटरों के लिए वास्तव में सीजन और भी मुश्किल हो जाता है।

इसी में उत्तर भारत में लंबे ठंड के सीजन के मैचों पर असर का मुद्दा जुड़ गया। ढेरों मैच बुरी तरह से प्रभावित रहे। कोहरे के कारण खेलना मुश्किल हो गया था। जम्मू, लाहली, चंडीगढ़, मोहाली, मेरठ और कानपुर जैसे कई शहर में मैच प्रभावित हुए- ऐसे दिन भी आए जब एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। यह मसला वास्तव में कोई नया नहीं- हर साल सर्दी है और मैच भी इसी तरह से रुक रहे हैं। जब सुनील गावस्कर, बीसीसीआइ की टेक्निकल कमेटी के प्रमुख थे, तो सिफारिश थी कि सर्दियों के दौरान (खासतौर पर 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच), उत्तर और मध्य भारत के कुछ शहरों में रणजी ट्राफी मैच न खेले जाएं।

इस तरह से नए सीजन का प्रोग्राम बनाते हुए ये सभी मुद्दे एक चुनौती की तरह क्रिकेट बोर्ड के सामने थे। बीसीसीआइ की शीर्ष काउंसिल बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई पर वहां भी ये बात सामने आई कि सीजन में मैच इतने हैं कि हर तरह से सही दिखने वाला कार्यक्रम धनाना आसान नहीं। पिछले रणजी ट्राफी सीजन के बाद फाइनल पहुंची मुंबई और विदर्भ ने कहा था कि सीजन ने थका दिया है।

दिन कम जबकि मैच बढ़ गए इसलिए जब बीसीसीआइ ने 2024-25 सीजन का प्रोग्राम घोषित किया तो हर जानकार ने उसे इस सवाल के साथ देखा कि क्या पिछले सीजन की दिक्कत को दूर किया जा सका है ? सीजन की शुरुआत होगी लाल गेंद क्रिकेट से और सबसे पहले दलीप ट्राफी खेलेंगे पांच सितंबर से। इस टूर्नामेंट के स्वरूप और घरेलू क्रिकेट में इसके महत्त्व पर लंबी बहस के बाद, अब दलीप टाफी का स्वरूप बदलेगा यह इंटर जोन टूर्नामेंट न हो कर, चार ऐसी टीमों के बीच खेला जाएगा। जिन्हें बीसीसीआइ की चयन समिति चुनेगी। स्पष्ट है कि इरादा खिलाड़ियों के उस बड़े पूल को मौका देने का है जो भारत के टेस्ट सीजन में खेलने के दावेदार हों।

रणजी ट्रॉफी के लिए पारंपरिक कर्टन-रेजर ईरानी कप एक अक्तूबर से शुरू होगा। 11 अक्तूबर 2024 से रणजी ट्राफी (प्लेट और एलीट) शुरू होगी और खास बात यह कि बदले स्वरूप

> बीसीसीआइ ने 2024-25 सीजन का प्रोग्राम घोषित किया तो हर जानकार ने उसे इस सवाल के साथ देखा कि क्या पिछले सीजन की दिक्कत को दूर किया जा सका है ? सीजन की शुरुआत होगी लाल गेंद क्रिकेट से और सबसे पहले दलीप ट्राफी खेलेंगे पांच सितंबर से। इस टूर्नामेंट के स्वरूप और घरेलू क्रिकेट में इसके महत्त्व पर लंबी बहस के बाद, अब दलीप टाफी का स्वरूप बदलेगा यह इंटर जोन टूर्नामेंट न हो कर, चार ऐसी टीमों के बीच खेला जाएगा।

के साथ। अब रणजी ट्राफी दो हिस्सों में होगी- पहले हिस्से में मैचों के पहले पांच राउंड जबकि बचे दो राउंड और नाक आउट मैच (क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल) दूसरे हिस्से में। पिछले सीजन में, रणजी ट्राफी के ज्यादातर मैच जनवरी और मार्च के बीच खेले गए थे जबकि इस बार रणजी ट्राफी अक्तूबर में शुरू हो रही है और सफेद गेंद क्रिकेट के दोनों टूर्नामेंट, इन दो हिस्सों के बीच फिट हो जाएंगे। पहले सैयद मुश्ताक अली ट्राफी और उसके बाद विजय हजारे ट्राफी होगी।

मैचों के बीच कम ब्रेक और कड़ाके की ठंड और बरसात में उत्तर भारत में मैचों को खेलने में दिक्कत और रुकावट के मुद्दे को बीसीसीआइ ने चार सदस्य वाले वर्क ग्रुप (सदस्य : चीफ कोच राहुल द्रविड़, एनसीए चीफ वीवीएस लक्ष्मण, सीनियर चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर और बीसीसीआइ महाप्रबंधक घरेलू क्रिकेट- अबे कुरुविला) के सामने पेश किया और इस ग्रुप की सिफारिश के बाद सीजन को दो हिस्सों में बांटने और मैचों के बीच अंतराल बढ़ाने को मंजूरी दी गई। अब मैचों के अंतराल चार दिन का होगा।

सीके नायडू ट्राफी (अंडर-23 क्रिकेट) में नई अंक प्रणाली भी लाई जा रही है। अगर यह कामयाब रही तो बीसीसीआइ इसे बाद में रणजी ट्राफी में (2025-26 सीजन से) ली सकती है।

सीके नायडू ट्राफी में एक और बदलाव- मैचों में टास खत्म और मेहगान टीम को अधिकार होगा बल्लेबाजीध गेंदबाजी चुनने का। नई अंक प्रणाली को शुरू करने की वजह- अंडर-23 स्तर पर बेहतर मुकाबले वाले प्रदर्शन को बढ़ावा देना है क्योंकि पिछले सीजन में अंडर-23 के कई मैच तो चार सत्र में ही खत्म हो गए थे जो खिलाड़ी के लंबे समय तक पिच पर टिकने की कला भूलने का संकेत बन रहा था।

स्वास्थ्य

'थायरॉइड'' मनमानी बढ़ा देगी मुसीबत

वर्ल्ड हेल्थ के एक शोध के अनुसार, थायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाले हॉर्मोन्स टी-3 और टी-4 शरीर में दिल की धड़कन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित करते हैं। लंबे समय तक थायरॉइड का अनियंत्रित रहना हृदय रोग का खतरा बढ़ा देता है। व्यक्ति को स्थायी रूप से अनिद्रा, बेचैनी और अवसाद जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लेकिन, अच्छी बात है कि दवा और स्वस्थ जीवनशैली की मदद से इसे मैनेज किया जा सकता है।

कैसे काम करता है यह ग्लैंड : तितली जैसे आकार वाला थायरॉइड ग्लैंड, गले के निचले हिस्से में होता है। इससे टी-3, टी-4 और टीएसएच यानी थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन का स्राव होता है। शरीर की कोशिकाओं व मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ठीक रखने में इन हॉर्मोन्स की बड़ी भूमिका होती है। इन सबका सीधा असर व्यक्ति की भूख, नींद, वजन और मनोदशा पर देखने को मिलता है।

जब थायरॉइड ग्लैंड धीमी गति से काम करता है और टी-3 व टी-4 का पर्याप्त निर्माण नहीं होता तो इसे हाइपोथायरॉइडिज्म कहा जाता है। वहीं जब यह ग्लैंड ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तो टी-3 और टी-4 हॉर्मोन अधिक मात्रा में खून में घुल जाते हैं। ज्यादातर लागों में हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षणरू एकाग्रता में कमी, उदासी, थकान, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, वजन बढ़ना, पीरियड्स में अनियमितता, कब्ज, रूखी त्वचा, बाल गिरना, गर्भपात या कंसीव न कर पाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, शरीर और चेहरे पर सूजन आदि।

हाइपरथायरॉडिज्म के लक्षण : वजन घटना, बेचैनी, दस्त, ज्यादा गर्मी लगना, हाथ- पैर कांपना, थकान, ज्यादा भूख लगना आदि। बच्चों में बढ़ता थायरॉइड : आजकल स्कूली बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। जन्म के समय थायरॉइड ग्लैंड ढंग से विकसित न होने या हॉर्मोन का स्राव ढंग से न होने पर ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में शिशु के मस्तिष्क का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। यही कारण है कि आजकल डॉक्टर जन्म के समय ही इसकी जांच करते हैं। असक्रिय जीवनशैली. व खानपान में लापरवाही से भी ऐसा होता है।

क्या कहता है आयुर्वेद : खुर्जा में पीएलआरडी हॉस्पिटल में वैद्य गोपालदत्त शर्मा के अनुसार, शुरुआत में इसे आयुर्वेदिक दवाओं से काबू कर सकते हैं, पर टीएसच 10 से ज्यादा हो जाए तो एलापैथिक दवा की जरूरत पड़ती है। हाइपोथायरॉइड के लिए कचनार के पेड़ की 20 ग्राम छाल को 80मिलीलीटर पानी में उबालें, जब पानी एक चौथाई रह जाए, तो इसे छानकर सुबह खाली पेट पिएं। सब्जियों को अच्छी तरह धोकर व छीलकर ही खाएं।

क्यों होता है ऐसा

यह जीवनशैली से जुड़ी समस्या है। असक्रिय जीवनशैली, व्यायाम की कमी के अलावा खानपान की गलत आदतों, जंक फूड, शराब व धूम्रपान का अधिक सेवन इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। आनुवंशिकता भी एक प्रमुख वजह है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स दवाओं का सेवन भी थायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन पर असर डाल सकता है।

जांच एवं उपचार

संदेह होने पर किसी अच्छी लैब से थायरॉइड फंक्शन टेस्ट करवाएं। कंसीव करने से पहले हर महिला को थायरॉइड जांच करवानी चाहिए। गर्भावस्था में इस हॉर्मोन के असंतुलन से एनीमिया, गर्भपात या जन्म के बाद शिशु की मृत्यु या उसमें मानसिक दुर्बलता की आशंका बनी रहती है।

दवा की है बड़ी भूमिका

थायरॉइड हार्मोन की रेंज के आधार पर डॉक्टर खुराक की मात्रा तय करते हैं, जिसे हर रोज लेना होता है। अगर डॉक्टर ने दवा की मात्रा बदली है तो चार से छह सप्ताह में जांच ज़रूर कराएं। सामान्य स्थितियों में छह महीने में जांच करानी चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म की स्थिति में भी दवाएं दी जाती हैं। सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। खुद से दवा बंद करने या खुराक बदलने की गलती न करें।

40 के बाद सभी को वर्ष में एक बार टेस्ट कराना चाहिए

1. क्या थायरॉइड महिलाओं को अधिक होता है? हां। दरअसल, किशोरावस्था, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज के दौरान उनके शरीर में हॉर्मोन संबंधी कई तरह के उतार- चढ़ाव आ रहे होते हैं। इसी क्रम में थायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स का स्राव भी घटने-बढ़ने लगता है।

2. क्या युवाओं और टीनएजर्स में थायरॉइड की समस्या बढ़ने लगी है?

ऐसा निश्चत नहीं कहा जा सकता। पहले जागरूकता के अभाव में लोग जांच नहीं करवाते थे। अब जांच अधिक हो रही है तो मामले भी अधिक सामने आ रहे हैं।

3. क्या मोटापे और दुबलेपन से इसका कोई संबंध है ? हाइपोथायरॉडिज्म की स्थिति में व्यक्ति का वजन 5 किलोग्राम तक बढ़ सकता है और हाइपरथायरॉयडिज्म की स्थित में इतना

बाक़ी पेज 11 पर

शेष.... प्रथम पृष्ठ

का यह प्रतिशत बढ़ता ही जाएगा और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमारे कानून संस्थान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आपराधिक राजनेताओं द्वारा नियंत्रित करना, यह कितना आश्चर्य की बात है कि दागी अपराधी राजनेता आज भी हमारे लोकतंत्र के लिए चुनौती बने हुए हैं।

हालाँकि, यह देखना हमारे शासकों का काम है कि हमारे राजनेता इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं या नहीं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आज हमारी केंद्र सरकार में 372 में से केवल 28 मंत्री ही होंगे। यह संख्या बढ़कर 72 तक पहुंच सकती है और हमारे हुक्मरानों को यह समझ लेना चाहिए कि जिस दिन ऐसा नजारा देखने को मिलेगा वह संभवतः हमारे लोकतंत्र का आखिरी दिन होगा।

पेज 2 का बाकी ....करीबी मित्र को

पूरा करने के लिए सहयोग की जरूरत है। भारत 2047 तक 'विकसित' राष्ट्र बनना चाहता है और बांग्लादेश, 'स्मार्ट' राष्ट्र। आर्थिक विकास व सामाजिक सामंजस्य दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। मनुष्यों (कथित अपराधियों समेत), मवेशियों, हथियारों और नशीले पदार्थों की सीमा पार अवैध आवाजाही पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

बांग्लादेश को भारत से ऋण की उम्मीद है। इसके लिए वह चीन से भी संपर्क करेगा। हालांकि हसीना की इस यात्रा के दौरान किसी नए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है, पर ऐसी घोषणा संयुक्त विज्ञप्ति में की जा सकती है। भारत परस्पर लाभ के लिए निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का तेजी से क्रियान्वयन चाहता है।

वर्ष 2010 से भारत ने बांग्लादेश को 7.36 अरब डॉलर का ऋण देने का वादा किया है। बांग्लादेश इस साल अप्रैल तक केवल 1.73 अरब डॉलर या वादे का 23 प्रतिशत ही उपयोग कर पाया है। मौजूदा भारतीय क्रेडिट लाइन की शर्तें बहुत सख्त हैं। जैसे, हर परियोजना के लिए लगभग 65-75 प्रतिशत सामान या - सेवाएं भारत से खरीदी जानी चाहिए, जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। हसीना ने सोनादिया बंदरगाह को विकसित करने के चीनी प्रस्ताव पर कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत इसकी भरपाई करेगा। भारत एक 'नई द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक है, और मोंगला समुद्री बंदरगाह में व्यापक भूमिका निभाना रहा है। हिंद-प्रशांत तक विस्तारित एक नया समुद्री मार्ग भी एजेंडे में है।

इसके अतिरिक्त, भारत का लक्ष्य समुद्री सहयोग को बढ़ाते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में श्सागरश परियोजना का विस्तार करना है। बांग्लादेश का लक्ष्य भूटान से अधिक जलविद्युत आयात करना है, जिसके लिए भारत की संहमति की आवश्यकता है। उम्मीद है कि भारत भूटान से बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाने के लिए अपने क्षेत्र के इस्तेमाल पर सहमत हो सकता है।

दोनों देशों के बीच सार्वजनिक परिवहन के लिए फेनी मोइत्री (मैत्री) पुल का जल्द उद्घाटन करने और रामपाल मोइत्री बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई खोलने के लिए चर्चा चल रही है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान 'दोनों परियोजनाओं को प्रतीकात्मक रूप से खोले जाने की उम्मीद है। दक्षिण त्रिपुरा जिले में भारत-बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु के माध्यम से यात्री आवागमन इस साल सितंबर तक शुरू होने वाला है। इसमें शामिल जटिलताओं को देखते हुए शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया है। उस यात्रा के दौरान इनमें से कुछ मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ज़ाहिर है, दोनों पड़ोसियों को मिलकर काम करना चाहिए, चाहे चीन का प्रभाव हो या न हो।

पेज 10 का बाकी....'थायरॉइड'' मनमानी बढ़ा देगी मुसीबत

ही वजन घट सकता है। लेकिन थायरॉइड की दवा लेने के बाद यह प्रक्रिया रुक जाती है और मरीज का वजन सामान्य हो जाता है।

4. थायरॉइड होने पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? सोयाबीन, फूलगोभी, बंदगोभी, ब्रोकली, खीरा व पालक का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। इन चीजों में मौजूद फाइबर ग्लैंड की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। साथ ही सोयाबीन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जिससे हॉर्मोन का स्राव धीमी गति से होता है।

5. क्या आयोडीन की कमी से भी यह समस्या होती है? पुराने समय में आयोडीन की कमी होने पर इस ग्लैंड में सूजन की समस्या होती थी, जिसे गॉइटर कहा जाता है। पर, जबसे देश में आयोडीनयुक्त नमक खाया जाने लगा है, यह समस्या समाप्त हो गई है।

6. क्या इसे पूरी तरह दूर किया जा सकता है?

अगर शुरुआती दौर में इसकी पहचान कर ली जाए तो कुछ हद तक इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। आमतौर पर नियमित जांच और दवाओं सेवन जरूरी होता है।

7. क्या वैकल्पिक चिकित्सा और घरेलू नुस्खों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है?

नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नियमित जांच व दवाओं का सेवन करना ही बेहतर रहता है।

8. थायरॉइड की दवा लेने का सही तरीका क्या है?

सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले दवा खा लें और उसके बाद आधे घंटे तक खाली पेट रहें। रोज दवा लें। अगर साथ में आयरन या कैल्शियम सप्लीमेंट भी लेते हैं तो थायरॉइड की दवा और इन विटामिनों के सेवन में कम से कम तीन घंटे का अंतराल ज़रूर रखें।

पेज..7 का बाकी.....लोस चुनाव के बाद

कांग्रेस अपने आंकड़े को 41 तक ले जाना चाहती है जबकि भाजपा 30 का आंकड़ा छूना चाहती है। यदि तीनों ही सीटें भाजपा भी ले जाए तो भी अंकगणित के हिसाब से प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की कोई खतरा नहीं है मगर उनके लिए तीनों सीटें जीत कर अपना आंकड़ा पहले के 40 से बढ़ा कर 41 करने की बड़ी चुनौती है।

तीनों ही सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं उन पर कांग्रेस पिछले कई चुनावों से हारती आ रही है। ऐसे में यदि वह भाजपा से कोई भी सीट छीन लेती है तो यह उसके लिए बड़ी जीत मानी जाएगी। देहरा में 15 साल से कांग्रेस नहीं जीती, यही कारण है कि यहां से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और आतंरिक गुटबाजी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। दोनों ही दल स्थानीय कारणों से अंदरूनी फूट का शिकार हैं ऐसे में इन तीन उपचुनावों की नतीजों को लेकर भी अब काफी दिलचस्पी बन गई है।

लोकसभा की चार सीटों के साथ-साथ उन छह कांग्रेसी विधायकों के क्षेत्रों में भी उपचुनाव हुए जिन्होंने भाजपा के पक्ष में क्रास वोटिंग करके कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया था। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी छह कांग्रेसी विधायकों, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे, को अयोग्य करार दे दिया था। इन छह विधायकों में से दो बड़सर से इंद्रदत लखनपाल व धर्मशाला से सुधीर शर्मा ही भाजपा के टिकट पर जीत कर फिर से विधानसभा में पहुंच गए जबकि लाहुल स्पीति से रवि ठाकुर, गगरेट से चौतन्य शर्मा, कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो व सुजानपुर से राजेंद्र राणा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए हार गए।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी चारों सीटों पर हार मिली मगर उसके लिए हल्की राहत यह रही कि कुछ समय पहले उसके अपने ही विधायक रहे छह उम्मीदवारों के सामने नए चेहरे उतारने पड़े और इन पर चार में उसे जीत मिल गई।

हाथरस : सत्संग के दौरान भगदड़ में 120 से अधिक की मौत

हाथरस के सिकंदराराऊ में चल रहे सत्संग में कथा समाप्त होने के बाद भीड़ रोकने पर हालात बेकाबू हो गए। चर्चा जहां बाबा की गाड़ी की चरणधूल लेने की जद्दोजहद थी, वहीं इसे भीषण गर्मी और उमस से सत्संगियों की परेशानियों से जोड़कर देखा जा रहा था। सत्संग में मौजूद वालेंटियरों ने भीड़ को बाबा के जाने के लिए रोक दिया। इससे वहां भगदड़ मच गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लोग एक दूसरे के ऊपर कूदते हुए बाहर भागने लगे। महिलाएं, बच्चे व पुरुष गिर गए, जिसमें भीड़ ने कुचल दिया।

हाथरस के सिकंदराराऊ में फुलरई स्थित एटा हाईवे के किनारे नारायण साकार हरि का सत्संग चल रहा था। यहां पर लाखों की तादाद में लोग आए थे। मंगलवार (02 जुलाई) की दोपहर करीब डेढ़ बजे कथा समाप्त हुई। इसके बाद कथावाचक निकलने लगे। इस पर वालेंटियरों ने भीड़ को रोक दिया। बाबा को जाने में करीब से 10 से 15 मिनट लग गए। पांडाल में भीषण गर्मी व उमस से बेहाल श्रद्धालु बाहर निकलने के लिए मारामारी करने लगे। इस दौरान वालेंटियर भीड़ को संभाल नहीं पाए। एक दूसरे एक ऊपर कूदते हुए भागने हाथरस के लगे। देखते ही देखते सत्संग स्थल पर भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि भगदड़ के कारण 121 लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल है।

वे देशभर में कब-कब भगदड़ से गई जान

सत्संग और मंदिरों के दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ की यह पहली घटना नहीं हैं। इससे पहले कई ऐसी घटनाएं घटी है। हाल के वर्षों में देश में मंदिरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ की कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं।

- स्लैब ढह जाने से 36 की मौत 31 मार्च 2023 रू इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई थी।
- वैष्णो देवी मंदिर में मची थी भगदड़ : एक जनवरी 2022 : जम्मू-कश्मीर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन लोग घायल हो गए।
- आंध्र में 27 तीर्थयात्रियों की मौत : 14 जुलाई 2015 : आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी जिले में पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ से 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई थी तथा 20 अन्य घायल हो गए थे।
- सतारा में कुचले गए श्रद्धालु : 25 जनवरी 2005 : महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंधारदेवी मंदिर में वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान 340 से अधिक श्रद्धालुओं की कुचलकर मौत हो गई थी।
- नदी के पुल टूटने की अफवाह : 13 अक्तूबर 2013 : मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
- गांधी मैदान में हादसा : 03 अक्तूबर 2014 : दशहरा समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोगों की मौत हो गई थी और 26 अन्य घायल हो गए थे।
- छठ पूजा के दौरान मची भगदड़ में 20 लोगों ने जान गंवाई : 19 नवंबर 2012 : पटना में गंगा नदी के तट पर अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल ढहने से भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई थी।
- हरकी पैड़ी घाट पर हुआ हादसा : आठ नवंबर 2011 : हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हरकी पैड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी।
- केरल में भी श्रद्धालुओं की जान : 14 जनवरी 2011 : केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु में एक जीप के सबरीमाला मंदिर के दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों से टकरा जाने के कारण मची भगदड़ में 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 40 घायल हो गए थे।
- कपड़े लेने को उमड़ी भीड़ : चार मार्च 2010 : यूपी के प्रतापगढ़ में पालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई थी। लोग स्वयंभू धर्मगुरु द्वारा दान किए जा रहे कपड़े और भोजन लेने पहुंचे थे।

पेज..12 का बाकी.....मंज़र पसमंज़र

है। लेकिन फिर भी ये घटनाएं पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं। खासकर पीएम मोदी की यात्रा से कुछ पहले हुई घटनाएं बताती है कि आतंकी तत्व अपनी मौजूदगी का अहसास कराने की कोशिश से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में चुनावों के दौरान उनकी तरफ से बाधा डालने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। 370 माह पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को हासिल विशेष दर्जे की समाति के बाद किए गए कार्यों का उल्लेख किया और बताया कि कैसे उसके बाद विकास का फल राज्य के लोगों एक ज्यादा आसानी से और ज्यादा मात्रा में पहुंच रहा है। लेकिन इस बारे में राज्य के लोगों की क्या राय है यह चुनावों से ज़ाहिर होगा।

लोकसभा चुनावों में वोटिंग का दशकों पुराना रेकॉर्ड टूटना जरूर एक उपलब्ध है है कि आतंकी को लाख कोशिशों के बावजूद प्रक्रिया के जरिए मुख्यधारा से जुड़ने को आम लोगों की इच्छा कम नहीं हुई है। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी भी सूरत में चुनाव की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई समयसीमा आगे न बढ़ने दी जाए।

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266
Publishing Date :30 June 2024 Posting Days : MON. - TUE. at N.D.P.S.O. New Delhi-110002R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र मीम.सीन.जीम

फिर गर्म होगा 'आरक्षण'?, फिर भटकता कनाडा, अब मिले राज्य का दर्जा

फिर गर्म होगा 'आरक्षण'?

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार के आरक्षण बढ़ाये जाने के कानून को रद्द कर दिया है। विगत वर्ष के नवम्बर महीने में बिहार की विधानसभा ने यह कानून राज्य में हुए जातिगत सर्वेक्षण के नतीजों के बाद किया था। पिछड़ों व अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की संख्या बढ़ी होने की वजह से उनका आरक्षण भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया गया था। परन्तु पटना उच्च न्यायालय का कहना है कि यह कानून संविधान के 14, 15 व 16 अनुच्छेदों की मूल भावना के खिलाफ है जिसमें समाज में बराबरी के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख है। संविधान प्रत्येक नागरिक को बराबरी की गारंटी देता है। इसके साथ ही संविधान यह भी गारंटी देता है कि समाज के शैक्षिक व सामाजिक तौर पर पिछड़े रहे व्यक्तियों को बराबरी पर लाने के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। इसीलिए जब 1990 में पिछड़े वर्ग की जातियों के लोगों पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का प्रावधान तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था तो उसके लिए संसद में कोई कानून नहीं बना था बल्कि सरकारी आदेश के तहत यह आरक्षण लागू किया गया था। परन्तु उसके बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण को रद करने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इसमें इन्दिरा साहनी बरक्स केन्द्र सरकार का मुकदमा विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि इस मुकदमे का फैसला करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि आरक्षण की सकल सीमा 50 प्रतिशत ही हो सकती है। 50 प्रतिशत में अनुसूचित जातियों व जनजातियों और पिछड़े वर्गों का आरक्षण ही सरकारी नौकरियों में हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला कानून बन गया। बिहार से पहले कई अन्य राज्यों की सरकारों ने भी आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ऊपर लांघनी चाही मगर वहां के सम्बन्धित उच्च न्यायालयों ने उसे रद्द कर दिया। मगर केन्द्र सरकार यदि चाहती तो बढ़े हुए आरक्षण को बरकरार रख सकती थी बशर्ते कि सम्बन्धित राज्यों के क़ानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में संसद की मार्फत दाखिल करा देती। इस अनुसूची में जो भी कानून चला जाता है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती जिस प्रकार कि तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है। केन्द्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई दशक पहले तमिलनाडु विधानसभा द्वारा आरक्षण का कोटा 69 प्रतिशत कर दिया गया था। तमिलनाडु की द्रमुक सरकार के इस कानून को केन्द्र ने नौवीं अनुसूची में डाल दिया था। परन्तु वर्ष 2023 में जब बिहार ने आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 75 प्रतिशत (10 प्रतिशत सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को मिला कर) किया था तो नीतीश बाबू विपक्षी महागठबन्धन के नेता थे जिसका केन्द्र की सत्तारूढ़ भाजपा से छत्तीस का आंकड़ा था लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नीतीश बाबू अब भाजपा नीत गठबन्धन में शामिल हैं। ऊपर से उच्च न्यायालय ने उनकी पिछली सरकार द्वारा बनाये गये कानून को रद्द कर डाला है। अतः इस मुद्दे पर अब राजनैतिक बाजार बहुत गर्म होगा। नीतीश बाबू की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने जब पिछली सरकार का मुखिया रहते बिहार के लोगों का जातिगत व आर्थिक सर्वेक्षण कराया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आये। सबसे बड़ा तथ्य यह निकल कर आया कि बिहार के हर तीन परिवारों में से एक केवल कुछ हजार मासिक की कमाई पर ही निर्भर रहता है। गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले 34 प्रतिशत बिहार निवासियों की दयनीय दशा का अन्दाजा लगाया जा सकता है। बिहार में पिछड़ों में भी दो वर्ग हैं। बिहार में आदिवासी बहुत कम संख्या में हैं क्योंकि 2000 में इस राज्य का बंटवारा होने के बाद अधिकांश आदिवासी बहुल इलाका झारखंड में चला गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि अपनी पार्टी का जनाधार बचाये रखने और सुशासन बाबू की अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए नीतीश बाबू अगला कदम कौन सा उठा सकते हैं।

> 1990 में पिछड़े वर्ग की जातियों के लोगों पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का प्रावधान तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था तो उसके लिए संसद में कोई कानून नहीं बना था बल्कि सरकारी आदेश के तहत यह आरक्षण लागू किया गया था। परन्तु उसके बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण को रद करने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

केन्द्र यदि बिहार के क़ानून को नौवीं सूची में डालती है तो यह समझा जायेगा कि वह भी जातिगत जनगणना के हक़ में है जबकि चुनावों के दौरान भाजपा ने इस मुद्दे पर केवल इतना ही कहा था कि वह जनगणना के ख़िलाफ नहीं हैं। मगर केन्द्र सरकार के पास वे आंकड़े मौजूद हैं जो 2011 में हुई जातिगत जनगणना के हैं। राहुल गांधी व समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव चुनावी प्रचार के दौरान यह भी कह रहे थे कि 2011 के आंकड़ों को केन्द्र सरकार सार्वजनिक करे और उसके बाद आरक्षण का नया फार्मूला संख्या के अनुसार जारी करे। राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे थे कि यदि गठबंधन की सरकार चुनावों के बाद आयी तो संसद में कानून बना कर वह आरक्षण को 50 प्रतिशत सीमा को ही बढ़ा देंगे लेकिन पटना उच्च न्यायालय के फैसले से यह मुद्दा अब फिर से संसद में गरमा सकता है और इस पर संसद के 24 जून से शुरू शुरू होने वाले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली बहस में क्या होता है। यह देखने वाली बात होगी।

फिर भटकता कनाडा

कनाडा में बढ़ते भारत विरोधी अलगाववाद की जितनी निंदा की जाए, कम होगी। भारत सरकार ने उचित ही कनाडा सरकार से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। फिर एक बार खून-ख़राबे को लालायित चंद ख़ालिस्तानी चरमपंथियों ने तथाकथित नागरिक अदालत आयोजित की है और बैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया है, तो क़तई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता। भारत ने कनाडाई उच्चायोग को बाकायदे एक राजनयिक नोट जारी करते हुए अलगाववादी तत्वों की ताजा हरकतों पर अपनी गंभीर आपति जताई है। कनाडा में भारत विरोध को जिस तरह से भड़काने की लगातार साजिशें हो रही हैं, उसमें कहीं न कहीं उस देश की मुख्यधारा की राजनीति का हल्कापन जिम्मेदार है, तभी तो घोषित आतंकी निज्जर को वहां की संसद में मौन ब्रद्धांजलि दी गई है। यह यही निज्जर है, जिस पर भारत में हत्या का आरोप था, जो मोस्ट वटिड आतंकियों की सूची में शामिल था। उसकी मौत पर कनाडा में आंसू बहाने वालों की संख्या निरंतर उग्र होती जा रही है, तो भारत सरकार को कुछ ज्यादा ही सचेत रहना चाहिए। अब यह बात कतई छिपी नहीं है कि जस्टिन टूडो की सरकार अलगाववादियों को खूनी खिलवाड़ का मौका दे रही है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अलगाववाद के प्रति नरमी खुद कनाडा के समाज पर भारी पड़ेगी। अलगाववाद का समर्थक पाकिस्तान आज किस मुकाम पर है, यह हर कोई देख रहा है। बेशक, दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दा कनाडा सरकार द्वारा अपनी धरती पर सक्रिय हिंसक तत्वों को छूट देने का है। दरअसल, कनाडा अपने ही इतिहास को भूल गया है। साल 1985 में 25 जून को मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को कनाडाई सिख आतंकियों ने बम विस्फोट से उड़ा दिया था। जमीन से 31,000 फीट ऊपरंबम विस्फोट हुआ था, जिसमें 268 कनाडाई, 27 ब्रिटिश व 24 भारतीय मारे गए थे। यह बमबारी आज भी विमानन आतंकवाद इके सबसे दर्दन दर्दनाक दुष्कृत्यों में से एक है। फिर 23 जून दहलीज पर है, पीड़ित परिजन अपनों की शहादत को हर साल की तरह इस बार भी याद करना चाहते हैं, लेकिन अलगाववादियों को यह चुभ रहा है। विडंबना देखिए, निज्जर को तो संसद में श्रद्धांजलि दी गई, मगर आतंकी हमले के शिकार बेगुनाहों को बाहर कहीं ब्रद्धांजलि देने पर आपत्ति हो रही है? ऐसे में, भारत सरकार ने आधिकारिक निंदा का सहारा लेकर दोटूक संदेश दिया है, जो कनाडा के कर्णधारों तक जरूर पहुंचना चाहिए।

> मोस्ट वटिड आतंकियों की सूची में शामिल था। उसकी मौत पर कनाडा में आंसू बहाने वालों की संख्या निरंतर उग्र होती जा रही है, तो भारत सरकार को कुछ ज्यादा ही सचेत रहना चाहिए। अब यह बात कतई छिपी नहीं है कि जस्टिन टूडो की सरकार अलगाववादियों को खूनी खिलवाड़ का मौका दे रही है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अलगाववाद के प्रति नरमी खुद कनाडा के समाज पर भारी पड़ेगी।

यह भी ग़ौर करने की बात है कि कनाडा में ही अच्छी नसीहत देने वाले कम नहीं हैं। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने साफ शब्दों में कहा है कि आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार विचारधारा अब भी उनके देश में कुछ लोगों के बीच जीवित है। कनाडाई संसद में बोलते हुए आर्य ने उचित ही कहा कि ख़ालिस्तान समर्थकों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाना यह दर्शाता है कि स्याह ताकतें फिर सक्रिय हो गई है। यहां हिंदुओं और उनके आयोजनों को निशाना बनाया जाने लगा है। कनाडा 1980 के दशक में ऐसी ही आग से गुजर चुका है, वहां की सरकार ने जब आतंकवाद का दर्द झेलने के बाद कड़ी कार्रवाई की थी, तब अलगाववादी आग काबू में आई थी, आज फिर वैसी ही जरूरत आन पड़ी है।

अब मिले राज्य का दर्जा

जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले उठी मांग लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद जम्मू-कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही वहां के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षा को संबोधित किया। उन्होंने न केवल वहीं जल्द चुनाव कराए जाने। का संकेत दिया बल्कि यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने में अब ज़्यादा देर नहीं है। बेशक ये दोनों मुद्दे जम्मू-कश्मीर के लोगों के दिल के करीब हैं, लेकिन इन पर ऐसी घोषणाओं से आगे बढ़कर काफी। कुछ करने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले ही दिन इन दोनों मसलों का ज़ि किया जो। इस बात का संकेत है कि सरकार की प्राथमिकता सूची में ये दोनों मुद्दे काफी ऊपर हैं। फिर भी ये घोषणाएं वहां तत्काल खास उत्साह नहीं जगा पाई तो उसकी। एक वजह यह भी है कि इनमें स्पष्टता की थोड़ी कमी पाई गई। प्रधानमंत्री की बातों दौरा से यह साफ नहीं हुआ कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दिए जाने की योजना है। इसमें दो राय नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगी

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTIMISSION

❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन :- 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173